लखनऊ

शुक्रवार, 8 मई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 254

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

# आर्यावर्त क्रांति

"हर बड़ा सपना पहले असंभव लगता है, लेकिन छात्र वही है जो असंभव को भी संभव बना दे।"

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 26° Low

## संक्षेप

### ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ: अमित शाह ने किया सेना के शौर्य को सैल्यूट, बोले- दुश्मन कहीं भी छिप जाएं, बच नहीं सकते

नई दिल्ली। पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट किया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को हमारे सशस्त्र बलों की अचूक प्रहार क्षमता की याद दिलाता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक ऐतिहासिक अभियान है, जो हमेशा हमारे दुश्मनों को हमारे सशस्त्र बलों की अचूक प्रहार क्षमता की याद दिलाता रहेगा। उन्होंने कहा, इतिहास इस दिन को हमारी सशस्त्र सेनाओं की सटीक मारक क्षमता, हमारी एजेंसियों की पैनी खुफिया जानकारी और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के उस दिन के रूप में याद रखेगा, जब ये सभी एकजुट होकर सीमा पार मौजूद आतंकवाद के हर उस ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए उठ खड़े हुए थे, जिसने पहलगाम में हमारे नागरिकों पर अपनी काली छाया डालने का दुस्साहस किया था। अमित शाह ने कहा कि यह दिन हमारे दुश्मनों के लिए यह भयावह संदेश लेकर आता रहेगा कि वे कहीं भी छिप जाएं, वे बच नहीं सकते। वे हर पल हमारी नजरों में और हमारी प्रचंड मारक शक्ति के निशाने पर हैं। शाह ने आखिर में लिखा, इस दिन मैं हमारे बलों के अद्वितीय शौर्य को सैल्यूट करता हूं।

### रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद में पूर्व CJI चंद्रचूड़ की प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मध्यस्थ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में संजय कपूर परिवार ट्रस्ट विवाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया। यह विवाद दिवंगत उद्योगपति की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच है। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की अध्यक्षता में और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने सभी पक्षों के मध्यस्थता के लिए सहमत होने के बाद यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने सभी हितधारकों से पूरे विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए खुले मन से मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया। न्यायाधीश ने आगे कहा कि सभी पक्षों को खुले मन और सकारात्मक भावना के साथ भाग लेना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी लंबी न चले। यह पारिवारिक विवाद है। इसे परिवार तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वे विवाद के बारे में कोई सार्वजनिक बयान न दें और न ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखें। न्यायालय ने इस बात पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने कहा कि वह प्रारंभिक मध्यस्थता रिपोर्ट का इंतजार करेगी और मामले की अगली सुनवाई अगस्त की शुरुआत में होगी। अदालत ने 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई में सौहार्दपूर्ण समझौते का सुझाव दिया था। उसने सोना ग्रुप पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद में सभी पक्षों से मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का आग्रह किया था, यह देखते हुए कि 80 वर्षीय वादी के साथ उत्तराधिकार की लंबी लड़ाई का कोई खास फायदा नहीं होगा और यह रचनात्मक भी नहीं होगी।

# भर्ती में न सिफारिश, न भ्रष्टाचार, सिर्फ योग्यता का सम्मान: सीएम योगी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर लोकभवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मिशन रोजगार" के अंतर्गत प्रदेश सरकार लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। पूरी प्रक्रिया में किसी को कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। परीक्षा के बाद भी किसी स्तर पर सिफारिश या अनैतिक साधनों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी साफ नीयत और स्पष्ट नीति का परिणाम है कि आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियां पैसों, जाति, मत, मजहब और क्षेत्र देखकर होती थीं, जिससे योग्य नौजवानों का शोषण होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योग्यता ही चयन का आधार बनी है। किसी योग्य अभ्यर्थी की जगह घूसखोर व्यक्ति व्यवस्था में आ जाता, तो वह अगले 30-35 वर्षों तक पूरे सिस्टम को घुन की तरह खोखला करता। इसलिए सरकार ने पहले दिन से ही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लीकेज की संभावनाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण आज यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।

### 15 दिनों के अंदर चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने नियुक्ति पत्र वितरण के नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपी के नौजवानों को निष्पक्ष, पारदर्शी व सहज प्रक्रिया से सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी। हमने अलग-अलग आयोगों व बोर्डों को जवाबदेही सौंपी और तकनीक का उपयोग कर हर योग्य नौजवान के साथ न्याय सुनिश्चित किया। इसी का परिणाम है कि हमने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर यह हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है।

### यूपी को बना दिया गया था भ्रष्ट-गुंडा-अराजक प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि याद कीजिए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश। देश-दुनिया में लोग यूपी का नाम सुनते ही शक की निगाह से देखते थे, दस कदम पीछे हट जाते थे। उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट, गुंडा और अराजक प्रदेश बनाकर हर यूपीवासी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अब आप कहीं भी जाएं, यूपी का नाम सुनते ही सामने वाले का चेहरा चमक उठता है, वह स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन का बदलाव और परिणाम भी उसी के अनुरूप हैं।

### आयुष के माध्यम से लाए जा सकते हैं चमत्कार

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष हेल्थ टूरिज्म को आकर्षित करने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है। इसके माध्यम से चमत्कार लाए जा सकते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को गांव-गांव में और बेहतर बनाना है। उपचार की पारंपरिक विधाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन के लिए किसानों से संवाद स्थापित करना है। आज 202 प्राध्यापक, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब आयुष विभाग को और गति देंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

### प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक बजट व अर्थव्यवस्था को तीन गुना किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक बजट व समग्र अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। यह सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला, किसानों को सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला और समाज के हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने वाला प्रदेश बन गया है।

### उद्योग की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपावर

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग बड़ा और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अनुकूल वातावरण व नीतियों से यूपी में लगातार बड़े निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, इन उद्योगों को मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध कराना व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा इसके अनुदेशकों की जिम्मेदारी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 150 से अधिक आईटीआई को आधुनिक बना दिया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हम कुशल प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन व अन्य टेक्नीशियन भी तैयार कर रहे हैं। आज नियुक्त होने वाले 272 ट्रेंड अनुदेशक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

# आतंकवाद को पालने वाले तंत्र को नष्ट करने के लिए भारत आज भी अडिग : पीएम मोदी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख को दोहराया। पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत न केवल आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उसे पोषित करने वाले पूरे तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर आज भी अडिग है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैन्य और आतंकी ढांचे के खिलाफ सैन्य अभियान के एक वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल बाद भी भारत आतंकवाद को हराने और उसे पोषित करने वाले तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प में पहले की तरह ही अडिग है। पीएम मोदी ने कहा कि एक साल पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेजोड़ साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिमाकत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरा देश भारतीय बलों के शौर्य को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसने हमारे सशस्त्र बलों के पेशेवर रवैये, तैयारी और समन्वित शक्ति को उजागर किया।'' पीएम मोदी ने कहा कि साथ ही इस अभियान ने भारतीय सुरक्षा बलों के बीच बढ़ती एकजुटता को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किए गए प्रयासों से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को रेखांकित किया। ऑपरेशन सिंदूर को तीनों रक्षा बलों द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ पश्चिमी सीमा पर सात से 10 मई, 2025 तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए अंजाम दिया गया था।

### अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दादी-पोता की मौत, एक मई को पिता बना था युवक

**सीतापुर।** सीतापुर जिले के बिसवां महमूदाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर बाइक सवार दादी पोता अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार दादी पोता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना रामपुर कलां क्षेत्र के ग्राम लौना निवासी 19 वर्षीय विशाल पांडेय अपनी दादी ज्ञाना देवी (60) को बाइक से लेकर महमूदाबाद जा रहे थे।तभी महमूदाबाद बिश्वा मार्ग पर एक बाइक एजेंसी के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार दोनो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहला में भर्ती करवाया। वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।

# 'कानून तभी सफल होगा, जब जनता सहयोग करेगी', जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर बोले भागवत

**मैसूर।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए जनता का सहयोग और दीर्घकालिक विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जाति आधारित राजनीति तभी खत्म होगी, जब समाज खुद जातिगत पहचान से ऊपर उठेगा।

आरएसएस प्रमुख ने मैसूरु में 'राष्ट्रीय विकास में सामाजिक समरसता की भूमिका' विषय पर व्याख्यान के बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहा कि समाज में धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द होना चाहिए। उन्होंने लोगों से नारेबाजी के बजाय बराबरी का व्यवहार करने की अपील की।

भागवत ने कहा, समाज जाति को याद रखता है, इसलिए राजनेता उसका फायदा उठाते हैं। उनका उद्देश्य वोट हासिल करना होता है। जब काम के आधार पर वोट नहीं मिलते, तो वे जाति के आधार पर वोट लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक और यूसीसी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस सरकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संगठन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी कानून तभी सफल हो सकता है, जब जनता उसका सहयोग करे। उन्होंने कहा, पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। नीति जरूरी है, लेकिन वह जनता के सहयोग से ही सफल हो सकती है। आपातकाल के दौरान अपनाए गए जनसंख्या नियंत्रण उपायों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि सख्ती से लागू की गई नीतियों के कारण लोगों में नाराजगी और राजनीतिक विरोध पैदा हुआ था।

# एनडीए के बिहार मंत्रिमंडल में 'पुत्र' उदय, नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत 3 पूर्व सीएम के लाल बने मंत्री

**पटना, एजेंसी।** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का गुरुवार को पूर्ण विस्तार हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाया जाना प्रमुख आकर्षण रहा। चौधरी के मंत्रिमंडल में अब तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे शामिल हैं - नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन। तीनों ने गुरुवार को शपथ ली। एनडीए ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। हवाई अड्डे से समारोह स्थल जाते समय, सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े लोगों ने मोदी के वाहन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। इंजीनियरिंग स्नातक निशांत कुमार, जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, ने जेडीयू नेतृत्व के लगातार आग्रह के बाद मंत्री पद की शपथ ली। खबरों के मुताबिक, निशांत कुमार ने शुरू में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, यह कहते हुए कि वे कोई भी औपचारिक पद स्वीकार करने से पहले एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी साख साबित करना चाहते हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसके 15 मंत्री हैं, जिन्होंने गुरुवार को शपथ ली। इनमें से अधिकतर वे मंत्री हैं जो पिछले साल नवंबर में एनडीए के विधानसभा चुनावों में शानदार वापसी के बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल थे।

# 'ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं, शुरुआत थी', पूर्व डीजीएमओ राजीव घई का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पूर्व सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इसे भारत की रणनीतिक यात्रा का एक निर्णायक क्षण बताया है। 7 मई, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद विरोधी भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिससे सैन्य कार्रवाई को पिछली सीमाओं से आगे बढ़ाकर नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार आतंकवाद को निशाना बनाया गया।

जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल घई, जो ऑपरेशन के दौरान डीजीएमओ के पद पर थे, ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हुए आज एक साल हो गया है, और तत्कालीन डीजीएमओ के रूप में, मैं इसे न केवल एक सैन्य अभियान बल्कि संभवतः भारत की रणनीतिक यात्रा का एक निर्णायक क्षण मानता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत सचेत और सुसंगत रूप से अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों और तरीकों से आगे बढ़कर नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार आतंकवाद को निशाना बनाया।

उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। एक साल बाद, हम न सिर्फ ऑपरेशन को याद करते हैं, बल्कि इसके पीछे के सिद्धांत को भी याद करते हैं। भारत अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा दृढ़ता से, पेशेवर तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने सरकार द्वारा निर्धारित स्पष्ट राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के साथ-साथ इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बलों को दी गई पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सटीकता, अनुपात और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ, यह एक राष्ट्र द्वारा संकल्प, जिम्मेदारी और रणनीतिक संयम का प्रतीक था।

# 'धार्मिक मामलों पर सवाल उठने लगे तो सैकड़ों याचिकाएं आ जाएंगी', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों पर सांविधानिक अदालत में सवाल उठाने लगेंगे, तो सैकड़ों याचिकाएं अलग-अलग रीति-रिवाजों पर आने लगेंगी, जिससे धर्म और सभ्यता दोनों पर गंभीर असर पड़ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ इस समय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। इनमें केरल का सबरीमाला मंदिर का मामला भी शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और उसकी सीमाओं पर भी विचार किया जा रहा है, जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े मामले भी हैं।इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत के साथ न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची शामिल हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की केंद्रीय संस्था ने 1986 में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें 1962 के उस फैसले को हटाने की मांग की थी, जिसमें बंबई बहिष्कार निवारण अधिनियम 1949 को रद्द कर दिया गया था। इस कानून के तहत किसी भी समुदाय के सदस्य को समाज से बाहर करने को अवैध माना गया था। 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्म के अनुसार, उनके धर्मगुरु किसी सदस्य को धार्मिक कारणों से समुदाय से बाहर कर सकते हैं। इसे उनके धर्म का हिस्सा माना गया था। इसलिए 1949 का कानून उस समय संविधान के अनुच्छेद 26(बी) के तहत दिए गए धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया, जो इस तरह के बहिष्कार को गैरकानूनी बनाता था।

वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन बदलाव चाहने वाले दाऊदी बोहरा समूह की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रथा किसी व्यक्ति के सामाजिक या गैर-धार्मिक आचरण के कारण की जाती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक संरक्षण नहीं मिल सकता। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई प्रथा धार्मिक पहलू भी रखती है लेकिन वह मूल अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, तो उसे सांविधानिक संरक्षण से बाहर रखा जा सकता है।

### न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति सुंदरेश ने क्या कहा?

इस दलील पर जवाब देते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, अगर हर कोई सांविधानिक अदालत के सामने कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों या धर्म से जुड़े मामलों पर सवाल उठाना शुरू कर दे, तो फिर उस सभ्यता का क्या होगा, जहां धर्म भारतीय समाज से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है?

# सुवेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, ममता बनर्जी को हराने की वजह से मेरे सहयोगी का मर्डर हुआ

**कोलकाता, एजेंसी।** अपने सहायक कर्मचारी चंद्रनाथ रथ की हत्या के एक दिन बाद, भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या का एकमात्र कारण यह है कि वह उनके कार्यकारी सहायक थे और उन्होंने भाबनीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। उन्होंने कहा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या का एकमात्र कारण यह है कि वह मेरे कार्यकारी सहायक थे और मैंने भाबनीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। सुवेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ रथ का पार्थिव शरीर मध्यग्राम के अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस हत्या की हम जितनी भी निंदा करें, वह काफी नहीं है। उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे मेरे सहयोगी थे और मैंने भाबनीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। यही उनकी हत्या का कारण हो सकता है। मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं और परिवार की मांग है कि इस हत्या के दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। पोस्टमार्टम से पता चला है कि उन पर चार गोलियां चलाई गईं... यह हत्या सुनियोजित थी। दिन की शुरुआत में, उन्होंने अपने कार्यकारी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला सुलझाने के प्रति विश्वास व्यक्त किया और कहा कि जांचकर्ता सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे बारासात अस्पताल पहुंचे, जहां रथ का पोस्टमार्टम किया गया।

# देवबंद पहुंचे सीएम, विकास के मंच से सियासी शक्ति प्रदर्शन, जुटी भीड़, कलक्ट्रेट में विरोध का एलान

आर्यावर्त संवाददाता

**सहारनपुर।** सहारनपुर में गुरुवार यानी आज का दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, वहीं दूसरी ओर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कलक्ट्रेट परिसर में आंदोलन का आह्वान किया है। विकास के दावों और विरोध की आवाज के बीच जिले में सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। पुलिस और प्रशासन दोनों कार्यक्रमों को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद में पहुंचकर मंच से विभिन्न योजनओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

देवबंद के जडौदा जट्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आगमन से पहले भारी भीड़ जुट गई है। पंडाल लोगों से भर गया है। भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण पार्टी के झंडों को लहराते हुए कार्यक्रम स्थल पर टोलियों के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंच रहे हैं। मंच पर जिले के भाजपा नेता प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। भीड़ बेसब्री से मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रही है। उधर जनसभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पुलिसकर्मी प्रत्येक गतिविधी पर नजर रखे हैं।

### देवबंद में मुख्यमंत्री की जनसभा पर भाजपा की नजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को देवबंद पहुंचेंगे, जहां वह कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन की ओर से जोरदार तैयारियां की गई हैं। भाजपा इस कार्यक्रम को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक शुरुआत के रूप में भी देख रही है। जनसभा स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।

### चंद्रशेखर आजाद ने खोला मोर्चा

दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कलक्ट्रेट परिसर में आंदोलन का एलान किया है। यह विरोध सर्किट हाउस रोड पर चल रही मकान तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा है।

प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था दिए बिना बेघर किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद खुलकर प्रशासन के खिलाफ उतर आए हैं।हालांकि प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों के लिए नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

### पुलिस-प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती

मुख्यमंत्री के दौरे और विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एक ओर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रशासन के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की घोषणा ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

राजनीतिक जानकार भी इसे विकास और जनहित के मुद्दों के बीच सीधे टकराव के रूप में देख रहे हैं। पूरे जिले की नजरें अब गुरुवार की घटनाओं पर टिकी हुई हैं।

### हाईवे पर रहेगा रूट डायवर्जन

मुख्यमंत्री की जनसभा को देखते हुए मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जामिया तिब्बिया चिकित्सा महाविद्यालय से घलौली फाटक के बीच करीब दस किलोमीटर का मार्ग बंद रहेगा। यह व्यवस्था बुधवार रात बारह बजे से लागू होकर गुरुवार शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन और कार्यक्रम में शामिल वाहनों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।

### ये रहेंगे वैकल्पिक मार्ग

सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जाने वाले भारी वाहनों को गागलहेड़ी, बड़कलां पुल, भगवानपुर और रुड़की के रास्ते भेजा जाएगा। देवबंद होकर मुजफ्फरनगर जाने वाले हल्के वाहन बरला तिराहा, बरला मार्ग और छपार के रास्ते आगे बढ़ेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने वाले हल्के वाहनों को रोहाणा टोल, घलौली, रणखंडी, गुनारसी, नूरपुर शुगर मिल चौराहा, भायला फाटक, कासिमपुर और जामिया तिब्बिया चिकित्सा महाविद्यालय के रास्ते भेजा जाएगा।

## मूल विद्यालय वापसी को लेकर बीएसए से मिला प्रा . शि . मि . संघ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, सुलतानपुर के जिलाध्यक्ष वृजेश पाण्डेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में आयोजित शिक्षामित्र सम्मान समारोह की सफलता पर बीएसए को बुके भेंट कर आभार जताया। जिलाध्यक्ष वृजेश पाण्डेय ने मांग रखी कि अन्य जनपदों की तरह सुलतानपुर में भी विकल्प भरने वाले इच्छुक शिक्षामित्रों की सूची जारी कर मूल विद्यालय वापसी का आदेश शीघ्र निर्गत किया जाए। महामंत्री पवन कुमार व कोषाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने बताया कि कई शिक्षामित्रों की तैनाती 70-80 किमी दूर होने से शिक्षण कार्य और जीवन-यापन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष प्रांजली श्रीवास्तव ने इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इस पर बीएसए उपेन्द्र गुप्ता ने तत्काल पटल बाबू अविनाश यादव को निर्देश दिए कि सभी विकास खंडों से पत्र के माध्यम से जल्द सूची मंगवाकर जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी हो सके। इस अवसर पर राजदेव यादव, नीरज कुमारी, वंदना तिवारी, दीप्ती, अंकित श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

## 'मैं डर गया था, मुझे लगता था कि बेटी जिंदा हो जाएगी', पुत्री के शव के साथ रहने के मामले में आया नया मोड़

आर्यावर्त संवाददाता

**मेरठ।** मेरठ के तेली मोहल्ला स्थित घर में प्रियंका विश्वास (33) की मौत के बाद उसके शव के साथ रहने वाले पिता उदयभानु विश्वास (76) पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने उदयभानु का मेडिकल कॉलेज में मानसिक परीक्षण कराया था। बुधवार को मनोरोग विभाग की टीम ने उसे डिस्चार्ज कर पुलिस को उसकी दिमागी हालत सामान्य होने की रिपोर्ट दी। शव मिलने के 25 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सदर बाजार थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ला स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद से सेवानिवृत्त लिपिक उदयभानु विश्वास के घर से 10 अप्रैल की रात उनकी बेटी का शव (कंकाल) बरामद किया गया था। जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उदयभानु ने बताया कि उसकी बेटी प्रियंका पीलिया से पीड़ित थी। उसने बेटी को झाड़-फूंक करने वाले शकील को कई बार दिखाया था। चार-पांच महीने पहले प्रियंका की मौत हुई थी। आरोपी के सही जानकारी न दे पाने के कारण अब तक प्रियंका की मृत्यु की तिथि स्पष्ट नहीं हो पाई है। पांच दिन उदयभानु बेटी के शव के साथ रहा और फिर हरिद्वार चला गया। कुछ दिन हरिद्वार में रहने के बाद उदयभानु मेरठ आया और फिर से बेटी के शव के साथ घर में रहा था। इसके बाद वह पांच दिसंबर को वह दोबारा हरिद्वार गया था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले परिजनों ने उसे जाते हुए देखा था। इसके बाद भी उदयभानु मेरठ आया था और बेटी के शव के साथ रहा था।

### जमानती धाराओं में दर्ज की प्राथमिकी

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 239 और 271 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है। धारा 239 में किसी घटना-अपराध को छुपाने व पुलिस को जानकारी न देने पर कार्रवाई की जाती है। धारा 271 के अंतर्गत जीवन के लिए खतरनाक रोग (संक्रामक बीमारी) फैलाने से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि शव कई महीने तक घर में रहने से बीमारी फैल सकती थी। दोनों ही अपराध में 6 महीने तक की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

### मैं डर गया था..मुझे लगता था कि बेटी जिंदा हो जाएगी

बुधवार को उदयभानु के घर पर दो ताले लगे हुए थे। उनके भतीजे विश्वजीत विश्वास घर के पास ही अपने घर के सामने बेंच पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि दोनों ताले पुलिस ने लगाए हैं। 10 अप्रैल को उदयभानु को हरिद्वार से वापस लौटने के बाद इसी बेंच पर बैठाया गया। उनसे पूछा कि प्रियंका कहां है वह कह रहे थे कि देहरादून है। काफी देर बाद उन्होंने बताया कि वह घर में बंद है। तब पुलिस को सूचना दी गई। कुछ दिन पहले वह उदयभानु से मिलने एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज गए थे। यहां उदयभानु से उन्होंने पूछा कि तुमने प्रियंका की मौत की बात क्यों छिपाई। तब उन्होंने कहा कि मैं डर गया था, मुझे लगता था कि बेटी जिंदा हो जाएगी। इसलिए वह कई बार उसे सिर और गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता था। विश्वजीत का कहना है कि उन्होंने कई महीने से घर की सफाई नहीं की थी। घर में काफी कूड़ा भरा था। हो सकता है कि वह इसी वजह से डर गए हों।

मानसिक परीक्षण की रिपोर्ट सामान्य आने के बाद उदयभानु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
-नवीना शुक्ला, सीओ सदर

## पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर और एंबुलेंस की टक्कर, एक की मौत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को फॉर्च्यूनर और एंबुलेंस की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हादसा कूरेभार थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 143 के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन तेज रफ्तार में थे जिसके चलते टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पीटीओ शैलेंद्र तिवारी ने तत्परता दिखाते हुए अपने सरकारी वाहन से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कूरेभार पहुंचाया जहां उनका उपचार शुरू कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी हैं, पीटीओ शैलेंद्र तिवारी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की हैं।

## जिम में लगे खुफिया कैमरे, ट्रेनर के फोन से मिले बड़े घरों की कई महिलाओं के . बरेली कांड की कहानी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**बरेली।** बरेली के सिविल लाइंस स्थित जिस अल्टीमेट फिटनेस जिम में प्री-वर्कआउट ड्रिंक में महिलाओं को नशा देकर यौन शोषण किया जा रहा था, वह एक जनप्रतिनिधि के भाई के भवन में संचालित है। जांच में चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

जनप्रतिनिधि के भाई ने इस कॉमर्शियल भवन का निर्माण कराने के बाद किराये पर उठा दिया है। इधर, आरोपी जिम संचालक अकरम और उसके भाई आलम के मोबाइल फोन से बड़े घरों की कई महिलाओं के वीडियो भी मिले हैं।

एक महिला डॉक्टर ने नशा देकर यौन शोषण करने, वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए जिम संचालकों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसके बाद पुलिस ने अकरम और आलम को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। उनको वहां से जेल भेज दिया गया था। दोनों भाइयों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए थे।

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि जिम में दोनों भाइयों ने खुफिया कैमरे लगा रखे थे। इन कैमरों के जरिये भी वे महिलाओं के वीडियो बनाने के बाद उनको पेन ड्राइव और मोबाइल फोन में ले लिया करते थे। इनके जरिये भी महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे।

### जिमों में महिला सुरक्षा, संचालकों के सत्यापन की मांग

अखिल भारत हिंदू महासभा ने बुधवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संगठन ने जिले के जिमों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संचालकों के पुलिस सत्यापन की मांग की। महासभा ने जिमों में महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं और जिम जिहाद का आरोप लगाया है।

मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कुछ जिमों में सनातन धर्म की महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हाल ही में एक जिम संचालक द्वारा डॉक्टर महिला से दुष्कर्म और मिनी बाइपास स्थित एक जिम में मारपीट जैसी घटनाओं का हवाला दिया गया। महासभा ने सभी जिम मालिकों और ट्रेनरों का पुलिस सत्यापन, प्रत्येक जिम में महिला ट्रेनर की तैनाती और महिला पुलिस अधिकारियों के विशेष दल के गठन की मांग की। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। जांच की जा रही है। दोनों के मोबाइल फोन में कुछ अन्य महिलाओं के भी वीडियो मिले हैं। इस रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों को भी ट्रेस किया जा रहा है।
- आशुतोष शिवम, सीओ प्रथम

## विधवा महिला ने लगाया बंधुआकला थाना की पुलिस पर आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** जनपद के बंधुआकला थाना की पुलिस पर लगा आरोप मारपीट में घायल महिला पीड़ति का ही उल्टा कर दिया गया चलान और मारपीट में शामिल चार लोगों के बजाय एक लोगों पर ही कार्यवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मझना निवासी एक विधवा महिला ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ति साधना मिश्रा अनुसार मारपीट करने वाले लोगों के उप्पर कार्य वाई करने के बजाय पीड़ति का भी किया गया चलान पीड़ति के अनुसार 16 अप्रैल 2026 को वह अपने बेटे विकास के साथ ई-रिक्शा से बाजार जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही अंकित पाण्डेय, अन्केत पाण्डेय तथा रविन्द्र पाण्डेय उर्फ मुन्ना ने ई-रिक्शा रुकवाकर गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर मारपीट की। महिला का आरोप है कि हमलावर उसके गले से सोने की चौन, पर्स में रखे 700 रुपये और बैंक पासबुक छीनकर फरार हो गए। महिला ने बताया कि 18 अप्रैल को आरोपी उसके घर पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे। गेट न खोलने पर कुंडी तोड़ दी गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने नाम नोट किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 25 अप्रैल को भी आरोपियों द्वारा घर पहुंचकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। पीड़ति ने बताया कि वह ई-रिक्शा और कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है। आरोप है कि 5 मई को उसकी 11 वर्षीय बेटी उन्नत मिश्रा दुकान पर बैठी थी, तभी आरोपी वहां पहुंचकर अभद्रता करने लगे। बच्ची के शोर मचाने पर महिला मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने चाकू और डंडे से हमला कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी।

## 16 दिन से गायब किशोरी की प्रेमी ने की हत्या

आर्यावर्त संवाददाता

**प्रयागराज।** मऊआइमा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक 17 साल की किशोरी का शव नहर किनारे बरामद हुआ। किशोरी सराय इनायत थाना क्षेत्र से लापता हुई थी। परिजनों ने पहले ही एक युवक और उसकी साथी पर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। शव मिलने के बाद अब हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की गहन जांच में जुटी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सराय इनायत थाना क्षेत्र के जमुनीपुर गांव निवासी लक्ष्मी नारायण पाल की पत्नी सुनीता पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी खुशी (17) को बहरिया थानाक्षेत्र के जलालपुर गांव का एक युवक अस्मित वर्मा अपनी साथी रिया के साथ 20 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे घर से बहला-फुसलाकर ले गया था। परिजनों के अनुसार किशोरी घर से लगभग 2000 रुपए नकद और लाखों रुपए के सोने-चांदी के गहने भी साथ ले गई थी। इन गहनों में सोने की चेन, अंगूठियां, झुमके, मनचली तथा चांदी के करधन, छागल, हाफ पेटी और पायल शामिल थे।

बुधवार यानी 6 मई की रात सराय इनायत पुलिस ने आरोपितों को पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ की। युवक ने बताया कि किशोरी की हत्या कर दी गई है। हरखपुर गांव स्थित शारदा सहायक नहर के बगल झाड़ी से लाश को फेंका गया है। इस पर पुलिसकर्मी हतप्रभ रह गए।

आज गुरुवार यानी 7 मई की सुबह किशोर को मऊआइमा ले जाया गया और फिर उसकी निशानदेही पर झाड़ी से किशोरी की लाश बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपित से पूछा तो उसने बताया कि किशोरी से उसका प्रेम संबंध था। लगातार वह शादी का दबाव बना रही थी।

आरोपितों ने बताया कि 20 अप्रैल को उसे लेकर शहर गया था। एक दिन बाद परिवार से मिलवाने की बात कहकर उसे बहरिया चलने को बोला गया। शाम को उसे लेकर निकला और जैसे ही अंधेरा हुआ शारदा सहायक नहर के पास उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को अभी उसके इस बयान पर पूरा यकीन नहीं है। सरायइनायत पुलिस का कहना है कि आरोपितों से फिर पूछताछ की जाएगी। इसमें और कौन-कौन शामिल हैं, इस बारे में पूछा जाएगा।

## ट्रेलर वाहन ने बाइक सवारों कों रौंदा, दो युवकों की मौत

**सुल्तानपुर।** देहात कोतवाली क्षेत्र के दोमुंहा-पखरौली मार्ग पर सोनबरसा गांव के पास गुरुवार को दोपहर बाद हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रेलर की टक्कर से हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक यूपी 44ए वाई 5818 नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक के चीथड़े उड़ गए। उसके शरीर के टुकड़ो कों बटोरा गया। मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान देहात कोतवाली के बभनगवा गांव निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वाहन और चालक की तलाश में जुटी है।

## जमीन पर कब्जे की कोशिश, शिकायतों के बाद भी प्रशासन मौन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** जमीन कब्जाने के आरोपों का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला लगातार प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे?

लक्ष्मणपुर निवासी बिंदु सिंह पत्नी कमलभान सिंह ने उपजिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनके पति द्वारा वर्ष 1990 में खरीदी गई जमीन पर 1992-94 में मकान बनवाया गया था और परिवार वर्षों से वहां रह रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग अब जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ता का आरोप है कि 1 अप्रैल 2026 को दबंग मौके पर पहुंचे और जबरन कब्जे का प्रयास किया। विरोध करने पर धमकी भी दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वर्षों पुराने मकान और स्पष्ट बैनामा होने के बाद भी कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी आखिर न्याय की उम्मीद किससे करे? प्रशासन की चुप्पी कहीं न कहीं दबंगों के हौसले बढ़ाने का काम कर रही है। सही है कि सरकारी फाइलों में तत्काल कार्रवाई के दावे जरूर दर्ज होते हैं, लेकिन जमीन पर पीड़ति आज भी न्याय के इंतजार में खड़ा दिखाई देता है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह संदेश जाएगा कि शिकायत करने से ज्यादा ताकत कब्जा करने वालों की चलती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन पीड़ति परिवार को न्याय दिलाता है या फिर यह मामला भी कागजी जांच और तारीखों के बीच दबकर रह जाएगा।

### मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टरों से रैगिंग

**प्रयागराज।** मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से महिला जूनियर डाक्टरों की रैगिंग से जुड़ा एक कथित वीडियो बृहस्पतिवार सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो का दैनिक लोकमित्र समाचार पत्र पुष्टि नहीं करता। करीब 58 सेकंड के इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टरों के साथ रैगिंग और उत्पीड़न किया जा रहा है। वीडियो में कुछ छात्राएं दिखाई दे रही हैं और कथित तौर पर जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट व मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी और शिकायत मिलने की बात से साफ इनकार किया है।

वायरल वीडियो में दो सीनियर छात्राएं और कई जूनियर छात्राएं नजर आ रही हैं। वीडियो बनाने वाली छात्रा का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई पड़ती है।

# अब नौकरी के लिए सिफारिश और अनैतिक दबाव की जरूरत नहीं पड़ती: सीएम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो



**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 202 प्रोफेसर, रीडर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स (आयुष विभाग) तथा 272 अनुदेशक (व्यावसायिक शिक्षा विभाग और 7 नर्स, हॉस्टल वार्डन और कंपाउंडर (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौकरी पाने के लिए अब सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। आयुष विभाग में वेरीफिकेशन में थोड़ी देरी जरूर हुई है। आवेदन, परीक्षा से परिणाम तक किसी सिफारिश या अनैतिक दबाव की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नीयत साफ, स्पष्ट नीति से परिणाम आने में देर नहीं लगती है। पिछले नौ साल में सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोई सोचता भी नहीं था कि यूपी में नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से होगी। हमने अलग-अलग आयोग को जवाबदेही के साथ काम दिया। तकनीक का बेहतर प्रयोग। किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय न हो जिससे अब निष्पक्ष भर्ती होती है।

पिछले 15 दिन में यह हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। 26 अप्रैल को 60 हजार पुलिस आरक्षियों की पासिंग आउट परेड। चार बड़ी नियुक्तियां हुईं। पिछले सप्ताह भी नियुक्ति पत्र दिया। आज यह चौथा कार्यक्रम है। आप का प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए स्वागत है। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा हिस्सा बनते हैं तो गति और प्रगति दोनों बढ़ेगी। दोनों में बेहतर संबद्ध हैं। इसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती है। पैसा लेकर भर्ती होती थी। नौजवाबनों का शोषण होता था। जाति, महजब, धर्म देखकर नियुक्ति होती थी। तो प्रतिभा हताश होकर पलायन करता था। यूपी की प्रगति बाधित होती थी। यूपी बीमारू राज्य बन गया था। यूपी अराजकता की ओर चला गया था। नौजवाबनों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था।

यूपी को गुंडा, भ्रष्ट और अराजक प्रदेश बना दिया गया था। आज ऐसा नहीं है। अब देश में कहीं भी चले जाइए और यूपी का नाम आएगा तो सामने वाले का चेहरा चमकता दिखेगा। वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखेगा। यूपी की अर्थव्यवस्था को तीन गुना किया गया। प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना किया गया। किसी राज्य से बेहतर यूपी की अर्थव्यवस्था है। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। यूपी सरप्लस स्टेट है। देश का ग्रोथ इंजन बना है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र, किसानों को इंसेंटिव, योजनाओं का लाभ देने वाला राज्य बना है। यूपी में हर क्षेत्र में प्रगति दिख रही है। नौजवानों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें गुंडे-माफियाओं को अपने गले का हार बना रही थीं। कोई बड़ा निवेशक नहीं आ रहा था। यूपी में गत वर्ष 4000 से ज्यादा बड़े निवेशक आए। 14 से बढ़कर 32 हजार उद्योग लगे हैं। जो कामचोरी करेगा वो दुर्गति से नहीं बच पाएगा। हमें तय करना है कि गति चाहिए या दुर्गति। यूपी में बहुत संभावनाएं हैं। अब यूपी की गिनती बॉटम थ्री से टॉप थ्री राज्य में हो रही है। आयुष सिर्फ आयुष नहीं, हेल्थ टूरिज्म को आयुष ही आकर्षित कर सकता है। इससे चमत्कार लाया जा सकता है। इस पर काम करना होगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को ठीक करना होगा। मेडसिनल प्लांट के लिए किसानों से बात करें। पंचकर्म को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी की विजय को आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने अलग-अलग बंटे विभागों को एक कर आयुष बनाया है।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएम योगी के योगदान को सराहा

इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया, जहां पहले दलाली और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 लाख से अधिक नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार के दी गई हैं। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि उनके विभाग ने पिछले 9 वर्षों में 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 7.5 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया है।

उन्होंने स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जैसे कि डीडीयूजीकेवाई के तहत ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना और टाटा के माध्यम से आईटीआई में उद्योग की मांग के अनुरूप नए ट्रेड्स (जैसे सोलर, एविएशन, 3डी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) शुरू करना। मंत्री अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश और उनके विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नए नियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह कियाऔर मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की तुलना हनुमान जी से करते हुए उनके योगदान की सराहना की।

## हनुमान मंदिर के बाहर चेन स्नेचिंग करने वाले चार शातिर गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** राजधानी के थाना वजीरगंज क्षेत्र में रकाबगंज स्थित हनुमान मंदिर के बाहर दर्शन करने आए श्रद्धालु से चेन छीनने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई पीली धातु की चेन, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ लखनऊ समेत अन्य जनपदों में लूट, झपटमारी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस के अनुसार 29 अप्रैल 2026 को वादी गौरव अग्रवाल निवासी टाटपट्टी कायस्थगली, यहियागंज थाना चौक ने थाना वजीरगंज में तहरीर देकर बताया था कि 28 अप्रैल की देर रात वह रकाबगंज स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए थे। इसी दौरान दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाश उनकी चेन छीनकर फरार हो गए। मामले में थाना वजीरगंज पर मुकदमा संख्या 98/2026 धारा 304 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी तथा सहायक पुलिस आयुक्त चौक के निर्देशन में थाना वजीरगंज पुलिस और सर्विलांस पश्चिमी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने लगभग 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान सुनिश्चित होने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेजीडेंसी के सामने से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों में हैदर अली, मोहम्मद साहिल, शारिक अली और इमरान शामिल हैं। सभी आरोपी मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार करते हुए बताया कि वे नशे और शौक पूरे करने के लिए लूट और झपटमारी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों के आसपास ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जो अकेले हों या जिनका ध्यान भटका हो। घटना वाले दिन भी उन्होंने मंदिर के बाहर रेकी कर पीड़ित को निशाना बनाया और बाइक से चेन छीनकर फरार हो गए।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई एक पीली धातु की चेन, घटना में प्रयुक्त काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल संख्या यूपी32 जेई 6439 तथा टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी संख्या यूपी32 केएक्स 3578 बरामद की है।

## ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर राष्ट्रवादी संदेश, सीएम योगी समेत भाजपा नेताओं ने बदली सोशल मीडिया डीपी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया है। मुख्यमंत्री योगी की नई डीपी और कवर फोटो को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आतंकवाद के खिलाफ भारत की आक्रामक नीति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर में 'सिंदूर' के प्रतीक को स्थान दिया है, जबकि कवर फोटो में ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमुखता से दर्शाया गया है। राजनीतिक और




रणनीतिक हलकों में इसे भारत की मजबूत सैन्य शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख के स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।7 मई 2025 की वह रात देश के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज हो चुकी है, जब भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। उसी रात भारत सरकार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर साझा करते हुए "Justice is Served" संदेश जारी किया था। इस अभियान ने दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ उसकी निर्णायक नीति का संदेश दिया।ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदलकर अभियान के प्रति सम्मान व्यक्त किया। देशभर में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तस्वीरों और प्रतीकों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।मुख्यमंत्री योगी की सोशल मीडिया कवर फोटो में दिखाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल डिजिटल बदलाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति का सार्वजनिक संदेश है।

ब्रह्मोस मिसाइल का उत्तर प्रदेश से विशेष संबंध भी सामने आया है। अब इसका निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है, जिसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से राज्य तेजी से रक्षा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। योगी सरकार लगातार यह संदेश देती रही है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सार्वजनिक मंचों से भारत की सैन्य शक्ति और ब्रह्मोस मिसाइल का उल्लेख करते रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि "ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के उस संकल्प की घोषणा थी कि आतंक का जवाब अब दुश्मन के दरवाजे पर दिया जाएगा।" उनके इस बयान को भारत की बदली हुई रक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की रणनीति के रूप में देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर बदली गई डीपी और कवर फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

## राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए लखनऊ पुलिस और डीएलएसए का संयुक्त अभियान शुरू, पीआरवी वाहनों को दिखाई गई हरी झंडी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

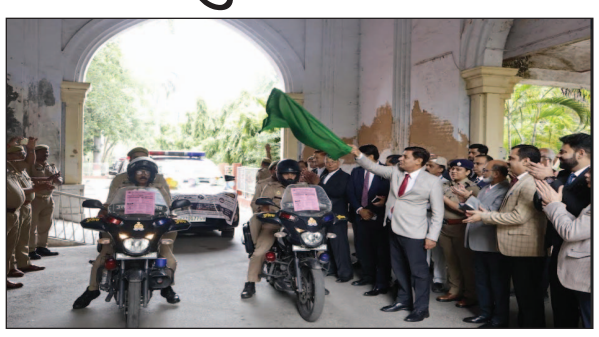



**लखनऊ।** आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता एवं न्यायिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर में लखनऊ पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के संयुक्त तत्वावधान में विशेष फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से शहर से लेकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता अभियान चलाने की शुरुआत की गई।कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह ने पीआरवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की पीआरवी (Police Response Vehicles) को रवाना किया गया, जो शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा न्यायिक सेवाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगी।कार्यक्रम में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निस्तारण संभव है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक लोक अदालत की उपयोगिता और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है, ताकि आमजन आसानी से न्याय प्राप्त कर सकें।इस दौरान नागरिकों को बैंक ऋण विवाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल से जुड़े मामलों सहित अन्य प्रकरणों के समाधान के लिए लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालतें लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का प्रभावी माध्यम बन रही हैं और इससे न्यायालयों पर भार कम होने के साथ ही लोगों को शीघ्र राहत मिलती है।फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम के बाद रवाना की गई पीआरवी टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों और दूरस्थ इलाकों में व्यापक विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस और डीएलएसए की संयुक्त टीमें घर-घर संपर्क, पंपलेट वितरण, जनसंवाद और सार्वजनिक उद्घोषणाओं के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी देंगी।विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं, हेल्पलाइन सेवाओं और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सरल और सुलभ न्याय व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सके।अधिकारियों ने कहा कि यह संयुक्त अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्यायिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य केवल कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि नागरिकों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना भी है।कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रकाश तिवारी, सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा तथा एडीसीपी (क्राइम) एवं लोक अदालत की नोडल अधिकारी किरन यादव सहित न्यायिक एवं पुलिस विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।

अखिलेश यादव के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पलटवार

## जनता ने सपा को नकारा इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठा रहे सवाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सपा प्रमुख के बयान पूरी तरह हताशा, निराशा और राजनीतिक पराजय की कुंठा का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा लगातार नकारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी अब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है।पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत और पारदर्शी लोकतंत्र है, जिसकी निष्पक्षता पर न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं के नियंत्रण में संचालित होती है। ऐसे में चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों और न्यायपालिका पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास भी है।न्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को यह समझना चाहिए कि उसकी हार का मुख्य कारण जनता का उससे मोहभंग है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया। पंकज चौधरी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस प्रमाण होता तो वह न्यायालय या चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करती, लेकिन बार-बार एक ही प्रकार के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करना सपा की पुरानी राजनीतिक शैली बन चुकी है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून-व्यवस्था, विकास और सुशासन के मुद्दों पर भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।पश्चिम बंगाल के संदर्भ में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि जहां-जहां विपक्षी दल सत्ता में हैं, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के कई उदाहरण सामने आते रहे हैं, जबकि भाजपा ने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का इतिहास अराजकता, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा रहा है।

## गोमतीनगर पुलिस ने 2 किलो से अधिक गांजे के साथ तस्कर को दबोचा

आर्यावर्त संवाददाता

**लखनऊ।** थाना गोमतीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 किलो 15 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 06 मई 2026 को उपनिरीक्षक कंचन तिवारी द्वारा फर्द बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना गोमतीनगर में मुकदमा संख्या 171/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया।पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अजीत तिवारी पुत्र अचल शंकर तिवारी निवासी ग्राम छतापुर कला थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को हैनीमैन चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाने वाले रास्ते पर गोमतीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी 06 मई की रात करीब 9:15 बजे की गई।तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2 किलो 15 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त था और बरामद गांजा को बेचने की फिराक में क्षेत्र में आया था।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। फिलहाल उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक कंचन तिवारी, उपनिरीक्षक गुरप्रीत कौर, उपनिरीक्षक हिमांशु द्विवेदी तथा आरक्षी सूर्यप्रताप सिंह शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

## डॉ. सूर्यकान्त टीबी आई.सी.यू. कमेटी के बने चेयरमैन

### टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के चलते डॉ. सूर्यकान्त को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी

आर्यावर्त संवाददाता

**लखनऊ।** किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त को राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश में गंभीर क्षय रोग (टीबी) मरीजों के बेहतर उपचार के लिए "टीबी कमिटेड आईसीयू" हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) एवं गाइडलाइन तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का चेयरमैन बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीइपी), स्वास्थ मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करेगी गम्भीर टीबी मरीजों के उपचार के लिए आईसीयू बनाने की मानक प्रणाली विकसित करेगी। ज्ञात रहे कि टीबी के वे गंभीर रोगी, जिन्हें आईसीयू की आवश्यकता होती है, उन्हें जनरल आईसीयू में नहीं रखा जा सकता हैय उनके लिए विशेष रूप से निर्मित आईसीयू की आवश्यकता होती है। डॉ. सूर्यकान्त कई वर्षों से टीबी से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख कार्य टीबी आईसीयू की स्थापना भी शामिल है। डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि टीबी के वे रोगी, जिनका ऑक्सीजन स्तर 90 प्रतिशत से कम होता है, उन्हें टीबी आईसीयू की आवश्यकता होती है। कुछ महीने पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि देश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में टीबी आईसीयू सुविधा युक्त कम से कम एक बेड अवश्य होना चाहिए। इसी क्रम में यह समिति बनाई गई है। केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानन्द ने टीबी मरीजों के बेहतर उपचार के लिए टीबी कमिटेड आईसीयू हेतु गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन बनाए जाने पर डॉ. सूर्यकान्त को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना भी की।

ज्ञात रहे कि आईसीएमआर द्वारा देशभर में जटिल टीबी के नए उपचार हेतु चलाए गए बीपाल प्रोजेक्ट के केजीएमयू के मुख्य पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। बीपाल प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही एमडीआर-टीबी के नए उपचार में नई दवाओं को शुरू किया गया है। इसके साथ ही वे टीबी से संबंधित कई चिकित्सकीय, शोध व सामाजिक समितियों के अध्यक्ष, सदस्य व सलाहकार भी हैं। डॉ. सूर्यकान्त ने ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी के क्षेत्र में केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी केयर चुना गया है। जिसके तहत टीबी मरीजों का उत्तम उपचार प्रदान किया जाता है। साथ ही पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन केंद्र के डा0 सूर्यकान्त संस्थापक प्रभारी भी है। जो उत्तर प्रदेश का का पहला सरकारी केंद्र है जहाँ पर साँस से सम्बंधित रोगियों का पूरी तरह से निःशुल्क उपचार किया जाता है। डा0 सूर्यकान्त के नेतृत्व में पोस्ट टीबी मरीजों जैसे टीबी के इलाज के बन्द होने के बाद भी खांसी/सांस व अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ऐसे मरीजों का इलाज भी किया जाता है। डॉ. सूर्यकान्त राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स (उत्तर प्रदेश के 9 राज्यों के लिए) के चेयरमैन के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। डॉ. सूर्यकान्त ने टीबी के बारे में 4 पुस्तकें हिन्दी में लिखी हैं, जिनमें से एक पुस्तक नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित 100 हिंदी पुस्तकों में शामिल रही। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना में डॉ. सूर्यकान्त टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अब तक 500 से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके उपचार, पोषण एवं देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2019 से ग्राम पंचायतों एवं स्लम क्षेत्र को गोद लेकर वहां टीबी उन्मूलन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अब तक सैकड़ों से अधिक टीबी से संबंधित विषय पर लेख प्रकाशित किए हैं तथा समय समय पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से निरंतर टीबी से आम जनमानस को जागरूक कर रहें हैं। टीबी उन्मूलन के लिए उनके प्रयास न केवल चिकित्सा सेवा तक सीमित हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर जागरूकता और मरीजों के पुनर्वास तक विस्तारित हैं। उनके नेतृत्व में किए जा रहे ये कार्य "टीबी मुक्त भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

# चुनाव परिणामों ने दिखाया नया राजनीतिक ट्रेंड, हिंदू भाजपा के साथ

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए मिला जुला चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ राज्यों में पार्टी को निराशा हाथ लगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे उल्लेखनीय सफलता भी मिली। इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा, जिसने कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। खास तौर पर असम और केरलम में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों ने प्रभावशाली जीत दर्ज कर यह संकेत दिया है कि इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा अभी भी इस गठबंधन के साथ बना हुआ है।

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की। राज्य में चुने गए 35 मुस्लिम विधायकों में से 30 संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा से संबंधित हैं। इनमें कांग्रेस के आठ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक शामिल हैं। यह परिणाम बताता है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर व्यापक भरोसा जताया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उम्मीदवार फातिमा तहलिया की जीत विशेष रूप से चर्चा में रही। उन्होंने कोझिकोड जिले की पेराम्ब्रा सीट पर माकपा नेता टीपी रामकृष्णन को पांच हजार से अधिक मतों से हराया। इस जीत के साथ वह पार्टी की पहली मुस्लिम महिला विधायक बन गईं। उनकी सफलता को मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

असम में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन और भी अधिक प्रभावशाली रहा। पार्टी ने राज्य में 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 ने जीत दर्ज की। इसके विपरीत कांग्रेस के अधिकांश गैर मुस्लिम उम्मीदवार हार गए और केवल एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी को सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता दर अत्यंत ऊंची रही। कांग्रेस के सहयोगी रायजोर दल को भी दो सीटों पर जीत मिली, जिनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार की थी, जबकि दूसरी सीट अखिल गोगोई ने जीती। अखिल गोगोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा माओवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है।

असम में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। गौरिपुर सीट पर कांग्रेस के अब्दुल सोबहान अली सरकार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार निजानुर रहमान को 19097 मतों से हराया। जलेश्वर सीट पर कांग्रेस के आफताब मोल्ला ने एआईयूडीएफ नेता शेख आलम को 109688 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। समागुरी में तंजिल हुसैन ने भाजपा के अनिल सैकिया को 108310 मतों से हराया। इसके अलावा अलगापुर कटलीछड़ा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का अंतर एक लाख से अधिक रहा। इन परिणामों ने यह संकेत दिया कि असम के कई क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से एकजुट हुए। हालांकि असम में कांग्रेस की इस सफलता के बावजूद एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब स्वयं समाप्त हो गई है। अजमल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है और यह स्थिति उन्हें दुखी करती है। उनका यह बयान असम की राजनीति में मुस्लिम मतों को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे "माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस" करार दिया था। आखिरकार उनकी बात सही साबित हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली, लेकिन दोनों सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से थीं। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की तुलना में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस ने दो मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से एक को जीत मिली। इन परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को साधने की रणनीति अपनाई थी और कुछ स्थानों पर उसे इसका लाभ भी मिला। मत प्रतिशत के आंकड़े भी इन चुनावों की राजनीतिक दिशा को स्पष्ट करते हैं। असम में भाजपा को 37.81 प्रतिशत मत मिले, जबकि कांग्रेस को 29.84 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दूसरी ओर केरलम में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिलाकर कुल 39.80 प्रतिशत मत मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि केरलम में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।

# छत्तीसगढ़ की जड़ी-बूटियों से महकेगा नारी शक्ति का स्वावलंबन

## औषधि पादप बोर्ड की नई कार्ययोजना से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं ग्रामीण महिलाएं

**धनंजय राठौर, अशोक चंद्रवंशी**

> वनांचल में बिखरे पारंपरिक ज्ञान को महज एक स्मृति न रहने देने के संकल्प के साथ बोर्ड ने इसे वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ के वनांचल की गोद में छिपी अमूल्य औषधि संपदा अब केवल स्वास्थ्य का आधार नहीं, बल्कि प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक स्वावलंबन का नया अध्याय बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन की जिस परिकल्पना को साकार कर रही है, उसे वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड धरातल पर उतार रहा है। गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, और शतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों से अर्क और उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।

वनांचल में बिखरे पारंपरिक ज्ञान को महज एक स्मृति न रहने देने के संकल्प के साथ बोर्ड ने इसे वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन स्थानीय वैद्यों और जानकारों का चिन्हांकन शुरू किया गया है, जिनके पास असाध्य रोगों के उपचार का अद्भुत ज्ञान है। बोर्ड का प्रयास इन महिलाओं को एक उचित मंच प्रदान करना है, ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिले और वे स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस विरासत का सम्मान है जिसे ग्रामीण महिलाओं ने सदियों से सहेजकर रखा है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक जड़ी-बूटी और जनजातीय ज्ञान को अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से नई पहचान मिल रही है। राज्य के वनों में छिपे औषधीय खजाने को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित कर, उसे आजीविका के साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा बदलाव तब दिखाई दे रहा है, जब जड़ी-बूटियों का संग्रहण करने वाली महिलाएं अब संग्राहक से आगे बढ़कर निर्माता की भूमिका में नजर आ रही हैं। बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, महिला स्व-सहायता समूहों को औषधि प्रसंस्करण (क्कह्म्शष्द्गह्यह्यद्बठ्ठद्द) के उन्नत गुर सिखाए जा रहे हैं। यह पहल न केवल औषधीय पौधों का संरक्षण कर रही है, बल्कि वनवासियों और लघु वन उपज संग्राहकों की आय में वृद्धि करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। छत्तीसगढ़ में 1500 से अधिक सक्रिय वैद्यों के ज्ञान को सहेजने और जड़ी-बूटियों के विपणन के लिए छत्तीसगढ़ जनजातीय स्थानीय स्वास्थ्य परंपराएं और औषधीय पादप बोर्ड सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह संस्था हर्बल उत्पादों की खेती, मूल्य संवर्धन, और मार्केटिंग में तकनीकी सहायता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है।

छत्तीसगढ़ में जड़ी-बूटी मूल्य संवर्धन एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से राज्य के समृद्ध वन संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करके उनके आर्थिक मूल्य को बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के तहत इन उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। जब ये महिलाएं वनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को साफ कर, सुखाकर उसे चूर्ण, अर्क या तेल के रूप में परिवर्तित करती हैं, तो उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस मूल्य संवर्धन का सीधा आर्थिक लाभ उनके बैंक खातों तक पहुँच रहा है, जिससे बिचौलियों का वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, और शतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों से अर्क और उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। 65 से अधिक लघु वन उपज प्रजातियों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) पर खरीदी और उनका प्रसंस्करण किया जा रहा है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख हर्बल स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है।

छत्तीसगढ़, जिसे 'बूटिगढ़' भी कहा जाता है, अपने घने जंगलों, विशेषकर बस्तर में 160 से अधिक प्रकार की दुर्लभ जड़ी-बूटियों का प्राकृतिक खजाना है। यहाँ की मिट्टी में अश्वगंधा, सर्पगंधा, गोक्षुरा (गोखरू), कुटकी और तिखुर जैसी औषधियां पाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। बाजार की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए बोर्ड ने विपणन (रूड्डह्म्द्मद्गह्लद्बठ्ठद्द) तंत्र को पारदर्शी बनाया है। प्रदेश के छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड को सशक्त करने के लिए प्रदर्शनियों और रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इन उत्पादों को सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्होकल फार लोकल और मुख्यमंत्री के लखपति दीदी अभियान को सफल बनाने में यह रणनीति संजीवनी का कार्य कर रही है।

जड़ी बूटियों को किचिन गार्डन, होम गार्डन में खिड़की, बालकनी, टेरिस पर गमलों, या अन्य कंटेनरों में कभी भी उगाया जा सकता है। कंटेनर गार्डनिंग या ग्रो बैग में जड़ी-बूटियां उगाने का एक फायदा यह भी है कि जड़ी बूटी को उसकी जरूरत के आधार पर मिट्टी, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश और नमी के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है तथा गमलों में उगाई गई प्रत्येक जड़ी-बूटी (हर्ब) को उसकी आदर्श स्थितियाँ दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से औषधीय पौधों की मदर नर्सरी विकसित करने की जिम्मेदारी महिला समूहों को सौंपी जा रही है। इससे दुर्लभ जड़ी-बूटियों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए बारहमासी रोजगार के द्वार खुल गए हैं, जिससे वनांचल से होने वाले पलायन पर भी अंकुश लगा है।

राज्य शासन का यह समेकित दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप बोर्ड केवल एक प्रशासक की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। सामूहिक नेतृत्व और संस्थागत सुधारों पर जोर देने से आज छत्तीसगढ़ की बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। वनांचल की महिलाओं के चेहरे पर उपजी मुस्कान एक समृद्ध और स्वावलंबी छत्तीसगढ़ की सच्ची तस्वीर पेश कर रही है।

**लेखक संयुक्त संचालक जनसंपर्क, सहायक जनसंपर्क अधिकारी रायपुर हैं**

## टिप्पणी

# मजदूरों के असंतोष

नोएडा में कारखाना मजदूर सड़क पर उतरे। वहां की घटनाओं ने उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिससे हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर आंदोलित हुए हैं। मजदूरों के असंतोष पर सहानुभूति से ध्यान दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में मजदूरों का उबलता असंतोष सोमवार को सड़कों पर छलक गया। हिंसा, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने वहां उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिस कारण हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर आंदोलित हुए हैं। वैसे, तो इन आंदोलनों के स्थल देश भर में फैले हुए हैं, लेकिन खास चर्चा हरियाणा में हुई आंदोलनकारी गतिविधियों की हुई। आखिरकार उनका असर हुआ, और हरियाणा सरकार ने आठ अप्रैल को सभी श्रेणियों के कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया। इस निर्णय का असर नोएडा में देखा गया।

कुछ ही दूरी पर एक जैसे काम के लिए अलग-अलग मजदूरी की बात उन्हें चुभी और वे भी आंदोलन पर उतर आए। वैसे भी एक विश्लेषण के मुताबिक 2016 से अब तक दिल्ली और हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी काफी कम बढ़ी है। दिल्ली में ये वृद्धि लगभग 90 फीसदी और हरियाणा में 89 प्रतिशत रही, जबकि उत्तर प्रदेश में इसमें महज 42.6 फीसदी का इजाफा हुआ है। यानी गुजरे एक दशक में हुई मुद्रास्फीति के अनुपात में यूपी में मजदूरी नहीं बढ़ी है। ऐसे में मजदूरों के असंतोष को समझा जा सकता है। इस बीच श्रम कानूनों की जगह श्रम संहिताएं लागू होने और आठ घंटे काम की सीमा हटाए जाने की वजह से मजदूर पहले मिली वैधानिक सुरक्षाओं से वंचित हो गए हैं।

उनकी पीड़ा को एक मजदूर की एक टीवी चैनल पर कही गई इस बात से समझा जा सकता है कि रोजाना 12 घंटे काम करने के बाद उन्हें महीने में 13 हजार रुपये मिलते हैं! अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखाना मालिकों और मजदूरों के बीच संवाद कायम करने के लिए एक समिति बनाई है। मगर साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश का शक भी जता दिया है। ऐसे में यह नहीं लगता कि मजदूर सरकार से किसी हमदर्दी की आशा कर सकते हैं। मगर ऐसे नजरियों से उस वक्त औद्योगिक शांति कायम करना कठिन होगा, जब श्रमिक वर्ग पर बढ़ते आर्थिक संकट की गहरी मार पड़ी है।

## ब्लॉग

# एग्री स्टैक: भारत की डिजिटल कृषि क्रांति

**डॉ. देवेश चतुर्वेदी**

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। इस क्षेत्र में कुल श्रमशक्ति का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा जुटा हुआ है। पिछले दशक में सरकार की ओर से उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण, खेती की लागत में कमी लाने, कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत अर्जित करने, जलवायु के अनुकूल ढालने और जोखिमों को कम करने की बहुआयामी रणनीति के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के ठोस प्रयास किए गए हैं।

केन्द्र प्रायोजित या केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के जरिए किसानों को विभिन्न सेवाओं या लाभों की निर्बाध, पारदर्शी और कुशल आपूर्ति संघीय या राज्य स्तर की सरकार की प्राथमिकता है। कुल कृषि भूमि का स्वामित्व और उस भूमि पर बोई गई फसलों का इतिहास किसी भी योजना के लाभ के लिए किसी भी किसान (चाहे वह मालिक हो, पट्टेदार हो या फिर बटाईदार हो) की पात्रता के आकलन की जरूरी शर्त है। हालांकि, देश भर में भूमि से संबंधित प्रशासन में पायी जाने वाली व्यापक भिन्नताएं एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं।

स्वामित्व और बुवाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित करने वाले एक मानकीकृत किसान डेटाबेस के महत्व एवं जरूरत को पहचानते हुए, सरकार ने वर्ष 2024 में डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की। किसानों के इस डेटाबेस को मजबूत सहमति तंत्र के साथ गतिशील रूप से अद्यतन किया जाता है। एग्री स्टैक, इस डिजिटल कृषि मिशन का एक प्रमुख स्तंभ है। यह अब इस मिशन के एक मौन लेकिन सशक्त परिवर्तनकारी स्तंभ के रूप में उभर रहा है। इसमें तीन विवरणी (रजिस्ट्री) – खेत, किसान और बोई गई फसल - शामिल हैं। एग्री स्टैक भारत की कृषि से जुड़ी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का इशारा करता है। एक ऐसा अध्याय, जो माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक 'विकसित भारत के सपने को साकार करने के लक्ष्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

खेत वाली रजिस्ट्री में भौगोलिक संदर्भों के आधार पर कृषि भूखंडों का डेटाबेस शामिल होता है। इनमें से प्रत्येक भूखंड को एक अनूठी कृषि आईडी प्रदान की जाती है। दूसरी परत में, प्रत्येक भूमि के मालिक किसान को एक अनूठी फार्म आईडी प्रदान की जा रही है। इस आईडी में स्वामित्व वाली प्रत्येक भूखंड से संबंधित जरूरी जानकारियों के साथ-साथ सह-स्वामित्व के मामले में हिस्सेदारी का उल्लेख भी शामिल है। यह डेटा अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) से गतिशील रूप से जुड़ा हुआ है ताकि विरासत, बिक्री आदि के कारण स्वामित्व में हुआ कोई भी बदलाव किसान रजिस्ट्री में अद्यतन हो जाए। तीसरी परत में प्रत्येक भूखंड पर बोई गई फसल का विवरण शामिल होता है। यह विवरण बुवाई पूरी होने के बाद प्रत्येक फसल के मौसम में किए गए डिजिटल/तकनीक आधारित फसल सर्वेक्षण के जरिए हासिल किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न समझौता ज्ञापनों के जरिए 35 राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी की है। इस डिजिटल मिशन को केन्द्र और राज्य के बीच मजबूत सहयोग के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें पूर्ण समावेशन सुनिश्चित करते हुए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। एग्री स्टैक एक संघीय डेटाबेस है जिसका स्वामित्व राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के पास है, लेकिन केन्द्र सरकार सेवाओं की आपूर्ति और डेटा विश्लेषण के लिए इसका उपयोग कर सकती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक किसान के लिए एक सत्यापित डिजिटल पहचान बनाना, उस पहचान को सटीक रूप से मैप किए गए भूखंड से जोड़ना और प्रत्येक मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को दर्ज करना है। यह स्टैक नियमों पर आधारित एवं स्वचालित सेवा वितरण को विभिन्न योजनाओं और भौगोलिक क्षेत्रों में संभव बनाता है। इससे किसानों को बार-बार अपनी पहचान, भूमि स्वामित्व या फसल के विवरण को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें गोपनीयता और डेटा संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए किसानों से संबंधित जानकारी तक पहुंच एक मजबूत सहमति तंत्र के जरिए होती है।

दशकों तक, कृषि संबंधी प्रशासन कागजी अभिलेखों और मैनुअल सर्वेक्षण पर बहुत अधिक निर्भर रहा। यह अक्सर नागरिकों के लिए उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का कारण बनता था। एग्री स्टैक इस पुरानी परंपरा से हटकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। किसानों की पहचान का डिजिटलीकरण करके और उन्हें भूमि एवं फसल के आंकड़ों से जोड़कर, यह भारतीय कृषि की एक विश्वसनीय और नई तस्वीर पेश करता है।

अब तक 9 करोड़ से अधिक किसान आईडी का सृजन इस सफर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये डिजिटल आईडी एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इससे किसानों को बार-बार सत्यापन के बिना कई सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है और लेन-देन की लागत कम हो जाती है। सरकारी एजेंसियों की दृष्टि से, ये आईडी लाभार्थियों की पहचान में होने वाली त्रुटियों को कम करते हैं और लाभ का सही लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने में सहायक साबित होते हैं। हालांकि, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि एग्री स्टैक की शुरुआत मुख्य रूप से किसानों को विभिन्न योजनाओं के लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने के इरादे से की गई है, लेकिन यह भूमि के रिकॉर्ड या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की जगह नहीं लेगा। भले ही अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) के साथ इसका जुड़ाव प्रामाणिकता सुनिश्चित करता हो।

वर्ष 2025-26 में, 24 राज्यों ने 600 से अधिक ज़िलों में लगभग 30 करोड़ भूखंडों पर मोबाइल उपकरणों, जियोटैगिंग और सैटेलाइट की मदद से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण पारंपरिक विधियों से हटकर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पारंपरिक विधियां अक्सर धीमी होती थीं और उनमें विसंगतियों या त्रुटियों की गुंजाइश अधिक रहती थी।

यह डेटा उपज का अनुमान लगाने, खरीद की योजना बनाने और बाजार से संबंधित पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। यह सूखे, बाढ़ या कीटों के कारण फसल पर पड़ने वाले दबाव की शीघ्र पहचान करके आपदा की तैयारी को भी ठोस बनाता है। किसानों के लिए, बेहतर डेटा समय पर एवं फसल-विशेष से जुड़ी सलाह और गड़बड़ होने पर त्वरित सहायता प्रदान करता है।

देश भर में भूमि से जुड़े प्रशासन में मौजूद विविधता को ध्यान में रखते हुए, इस संरचना में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप इसे अनुकूलित करने का अंतर्निहित लचीलापन है। साथ ही, अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने हेतु सामान्य मानकों को बनाए रखा गया है ताकि राज्यों और केंद्रीय प्रणालियों के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान संभव हो सके।

उदाहरण के तौर पर, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां दशकों से भूमि के रिकॉर्डों को अद्यतन नहीं किया गया है और पूर्वजों के नाम अभी भी दर्ज हैं। भूमि के रिकॉर्डों को अद्यतन करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच, मृतक मालिकों के नाम पर दर्ज भूमि पर खेती करने वाले उत्तराधिकारी किसानों को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन के बाद किसान आईडी जारी किया जा सकता है ताकि लाभों की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। जहां भी राज्य के कानून अनुमति देते हैं और राज्य सहमत होते हैं, वहां मजबूत स्वामी-प्राधिकरण तंत्र के साथ, बटाईदारों और किरायेदार किसानों को भी विशिष्ट योजना के लाभों को हासिल करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में, जहां सामुदायिक स्वामित्व का वर्चस्व है, भू-निर्देशांक-आधारित प्रमाणीकरण प्रथागत रीति-रिवाजों को बाधित किए बिना समावेशन की अनुमति देता है। किसानों के लिए, डिजिटल व्यवस्था का मतलब है कम फॉर्म भरना, स्थानीय कार्यालयों में कम चक्कर लगाना और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंचने में अधिक पारदर्शिता। भूमि के स्वामित्व और फसलों के इतिहास के अद्यतन विवरणों वाले विश्वसनीय डिजिटल रिकॉर्ड बैंकों और बीमाकर्ताओं को जोखिम का आकलन करने और किसानों की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने में समर्थ बनाते हैं। एग्री स्टैक में किसान संगठनों को मजबूत करने की क्षमता है। सत्यापित डेटा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उपज एकत्रित करने, बेहतर कीमतों के लिए बातचीत करने और कार्यशील पूंजी तक अधिक आसानी से पहुंच हासिल करने में मदद कर सकता है।

भूमि से जुड़े डेटा को फसलों की बुवाई और मिट्टी की सेहत से संबंधित विवरणों से लैस करने से कृषि के विस्तार में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है, क्योंकि अब किसानों की जरूरतों के अनुरूप सलाह तैयार और प्रसारित की जा सकती है। वह भी बहुत कम लागत पर। किसान स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बुवाई के सर्वोत्तम समय, सिंचाई कार्यक्रम, पोषक तत्वों के प्रयोग और कीट प्रबंधन के बारे में व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

एग्री स्टैक शासन की प्रक्रियाओं में सुधार लाने और साक्ष्य-आधारि व डेटा-संचालित नीति निर्माण को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रावधान के कारण नीति निर्माताओं के पास फसल पैटर्न पर नजर रखने, आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर का अनुमान लगाने और मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने हेतु सटीक और समय पर डेटा उपलब्ध होता है।

एक बार किसान की पहचान, भूमि के स्वामित्व और बोई गई फसल का डिजिटल सत्यापन हो जाने के बाद, नकद या वस्तु के रूप में सब्सिडी वितरण, फसल बीमा, खरीद या ऋण आदि से संबंधित लेनदेन डिजिटल रूप से सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। आधार-आधारित भुगतान गेटवे लाभ को सही लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित करते हैं। यह संशोधित प्रणाली सार्वजनिक व्यय का स्पष्ट डिजिटल रिकॉर्ड बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है।

यह देखा गया है कि केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और कुछ मामलों में तो एक ही मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने भी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपने-अपने किसान डेटाबेस विकसित किए हैं। एग्री स्टैक एक साझा लेकिन सार्वभौमिक डिजिटल माध्यम विकसित करके इस तरह के स्व-निर्मित डेटाबेस की सीमाओं को तोड़ता है ताकि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारी समितियां, राजस्व, खाद्य, उर्वरक, ऋण और बीमा प्रणालियां एक ही सत्यापित डेटा का उपयोग करके कार्य कर सकें। इससे न केवल परिचालन संबंधी दक्षता बेहतर होती है, बल्कि किसानों पर विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए कई पोर्टलों पर पंजीकरण करने का बोझ भी कम होता है। कई राज्यों ने एग्री स्टैक के उपयोग को सफलतापूर्वक लागू किया है। छत्तीसगढ़ ने पिछले खरीफ सीजन के दौरान एमएसपी आधारित धान की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण सुचारू रूप से करने हेतु एग्री स्टैक का उपयोग किया। मध्य प्रदेश ने पीएमएएसएचए के तहत सोयाबीन किसानों को मूल्य घाटे के आधार पर सहायता प्रदान करने हेतु इस डेटाबेस का उपयोग किया। महाराष्ट्र आपदा राहत सहित अपने सभी डीबीटी आधारित लाभों के लिए एग्री स्टैक का उपयोग कर रहा है।

# शादी वाले घर में फैला मातम, डोली के बाद उठीं अर्थियां... हमीरपुर के एक परिवार में चीख-पुकार

आर्यावर्त संवाददाता

**हमीरपुर।** उत्तर प्रदेशके हमीरपुर जिले में रात को हुए दिल दहला देने वाले नाव हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। यहां नाव यमुना नदी के बीच में पलट गई, जिसके चलते उसमें सवार 9 लोग डूब गए। इस हादसे में किसी तरह एक पुरुष समेत 2 बच्चे तैरकर किनारे आ गए, लेकिन एक महिला सहित 5 बच्चे लापता हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर डेरा डाल दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से 11 घंटों के रेस्क्यू अभियान के बाद एक महिला और दो बच्चों के शव नदी से बरामद कर लिए गए। वहीं, 4 बच्चों की तलाश के लिए अभी भी अभियान जारी है।

कैसे बिगड़ा नाव का संतुलन?

मामला जिले के कुरारा थाना

क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का है, जहां रहने वाले शराजू की बेटी अंजली की मंगलवार को शादी थी। बुधवार को विदाई के बाद शाम करीब 6 बजे रिश्तेदारी में आए 9 लोगों को विष्णु अपनी पत्नी के साथ नाव पर सवार होकर यमुना पार अपने खेत में तरबूज और खरबूज खिलाने के लिए ले गए। वहां खाने के बाद सभी ने कई फल तोड़कर नाव में लाद लिए और वापस घर आने लगे।

आधे रास्ते में यमुना नदी में अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई, जिसमें नाव चला रहे धीरू ने तैरकर खुद को बचाते हुए विष्णु और पारुल को बचा लिया, लेकिन बाकी 6 लोग पानी में लापता हो गए। इनमें से एक महिला और दो बच्चों के शव आज सुबह बरामद कर लिए गए हैं।

### डोली के बाद घर से उठीं अर्थियां

श्रीपाल की बेटी की शादी थी, जिसके चलते आसपास के सारे रिश्तेदार शादी में जमा हुए थे। घर में मंगल गीतों के साथ बेटी को विदा किया गया और रिश्तेदारों को तरबूज और खरबूज खिलाने की बात हुई। राजू की बारी यमुना नदी के पास स्थित थी, जहां तरबूज और खरबूज भारी मात्रा में लगे थे। राजू के चाचा का लड़का विष्णु अपनी पत्नी ब्रजरानी सहित 8 बच्चों को नाव से लेकर यमुना पार खेत में चला गया। वहां से उन्होंने भारी मात्रा में खरबूज और तरबूज नाव में रख लिए और सभी को लेकर वापस आने लगे। नाव में वजन ज्यादा होने से उसका संतुलन बिगड़ गया और सभी नदी में डूब गए। हालांकि नाव चला रहे धीरू ने दो लोगों को बचा लिया, लेकिन बाकी सब लापता हो गए। आज तीन लोगों के शव नदी में रेस्क्यू के दौरान मिल गए, जिसके बाद घर में मातम फैल गया है। जिस घर से कल एक डोली उठी थी, वहां से आज तीन अर्थियां उठ रही हैं।

### रेस्क्यू में लग रहा समय

नाव डूबने के चलते 6 लोगों के नदी में लापता होने की जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम, एसपी सहित जिले के अधिकारी पहुंच गए और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों को भी तुरंत बुला लिया गया। कई जिलों से टीमों के आने के बाद रात में ही सर्च लाइट की रोशनी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरे के चलते कोई सफलता नहीं मिली।

आज सुबह से तेज हवाओं और बारिश ने भी रेस्क्यू अभियान में खलल डाल दिया। इसके बावजूद एक महिला और दो बच्चों के शवों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तीनों के शव नदी में ही मिले हैं। शवों को देखकर गांव में मातम पसरा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। बाकी लोगों की तलाश जारी है।

# मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, दूसरा फरार

आर्यावर्त संवाददाता

**जौनपुर।** जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक हिस्ट्रीशीटर रुस्तम घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। , उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। रुस्तम पर जौनपुर और आजमगढ़ में लूट, चोरी और हत्या के प्रयास सहित एक दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं।यह घटना गुरुवार रात बरसठी और रामपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई। पुलिस के अनुसार बरसठी थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव और रामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ परियत तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिना नंबर प्लेट की काले रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक पर दो संदिग्ध युवक आलमगंज की तरफ से आ रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने महमूदपुर बैरी पट्टी तिराहे पर घेराबंदी कर दी। संदिग्ध बाइक मौके पर पहुंची, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।मुठभेड़ के दौरान बाइक चला रहा बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका दूसरा साथी झाड़ियों के रास्ते भाग निकला। घायल बदमाश की पहचान सहाबुद्दीनपुर, थाना गौराबादशाहपुर निवासी रुस्तम पुत्र मुस्लिम के रूप में हुई।पुलिस ने घायल रुस्तम के कब्जे से एक 32 बोर का देशी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की सुपर स्प्लेंडर बाइक बरामद की।

# हिंसा पर उतर आयी है टीएमसी : सांसद रवि किशन

आर्यावर्त संवाददाता

**जौनपुर।** गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने जौनपुर में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताकर ममता बनर्जी को हराया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि ममता बनर्जी को 15 साल से लग रहा था कि उन्हें कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही है और हिंसा पर उतर आई है। उन्होने ने टीएमसी पर लूट, माफिया और गुंडों के सहारे सरकार चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसीअब अपना असली चेहरा जनता को दिखा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुवेंदु अधिकारी पर चार गोलियां चलाई गईं और रोज हत्याएं हो रही हैं।उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। सांसद ने कहा कि अब समय बदल गया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है और नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से गुंडई और बदमाशी बंद करने का आग्रह किया। रवि किशन ने आगे कहा कि सरकार गठन होते ही पुलिस ऐसे लोगों को खोज-खोज कर कटघरे में खड़ा करेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी, जो फांसी तक हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा की सरकार आने के बाद बांग्लादेश भागने के रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने टीएमसी से हत्याओं का तांडव बंद करने की अपील की।

# मुरादाबाद में छात्रा के बुर्का पहनने पर हुई थी एफआईआर, कोर्ट से मिली जमानत, जज बोले– कोई ठोस सबूत नहीं

आर्यावर्त संवाददाता

**मुरादाबाद।** उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना इलाके में नाबालिग छात्रा के धर्म परिवर्तन और 'ब्रेनवॉश' के चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी युवती को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति ने आरोपी छात्रा फातिमा की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। गौरतलब है कि आरोपी फातिमा पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के बयानों के अतिरिक्त रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया आरोपी की इस अपराध में संलिप्तता पूरी तरह स्थापित हो सके। न्यायालय ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया कि आरोपी के फरार होने की संभावना

बेहद कम है और उसने जांच व ट्रायल में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

बिलारी का मामला तब तूल पकड़ गया था, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनते हुए देखा गया था। इसके बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने धर्मांतरण की धाराओं में केस दर्ज किया था। अब उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के अभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को राहत दी गई है।

### वीडियो वायरल होने के बाद गरमाया था मुद्दा

मुरादाबाद जनपद के बिलारी इलाके में यह मामला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर से शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ छात्राएं आपस में बातचीत करती नजर आ रही थीं। आरोप था कि फातिमा ने पीड़िता को बुर्का (हिजाब) पहनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा था कि "तुम इसमें अच्छी लगोगी।"

वीडियो में छात्रा को बुर्का पहनते हुए भी देखा गया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर काफी विवाद हुआ था। परिजनों और कुछ स्थानीय संगठनों ने इसे योजनाबद्ध तरीके से किया गया धर्मांतरण का प्रयास बताया था। इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी नाबालिग बहन का ब्रेनवॉश कर उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

### कैसे मिली जमानत?

पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि, मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा, तो बचाव पक्ष ने दलीलों में इसे केवल सहेलियों के बीच की सामान्य बातचीत और स्वेच्छा से पहना गया वस्त्र बताया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केवल बयानों के आधार पर किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है, विशेषकर जब जांच में सहयोग की गारंटी दी गई हो। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने शर्तों के साथ फातिमा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली, जो इस विवादित मामले में आरोपी पक्ष के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

# मथुरा में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए दो बदमाश, बावरिया गिरोह के थे दोनों सदस्य, 30 लाख का डाला था डाका

आर्यावर्त संवाददाता

**मथुरा।** मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के टैंटीगांव में बीती 23 अप्रैल की रात एक बड़े डकैती कांड को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। यह मुठभेड़ बृहस्पतिवार सुबह हुई, जिसमें दोनों आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी धर्मवीर उर्फ लंबू और अलवर निवासी राजेंद्र उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। दोनों कुख्यात बावरिया गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये नकाबपोश बदमाश 23 अप्रैल की रात टैंटीगांव में व्यवसायी अजय अग्रवाल के घर में घुस गए थे।

उन्होंने घर में मौजूद लोगों को धमकाकर करीब 30 लाख रुपये की नकदी और जेवरात लूट लिए थे। इस घटना के बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी।

मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह इन दोनों वांछित अपराधियों को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

एसएसपी ने बताया कि व्यापारी के घर वारदात देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दोनों घायल हुए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इस कार्रवाई के दौरान दो सिपाही भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, मारे गए दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और गंभीर रहा है। धर्मवीर उर्फ लंबू, जो राजस्थान के भरतपुर का निवासी था, पर विभिन्न थानों में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। उसके खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई थानों में करीब 16 मामले दर्ज थे, जिनमें कई में वह वांछित चल रहा था।

इसी तरह, राजेंद्र उर्फ पप्पू, जो अलवर का रहने वाला था, पर भी कई वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसके खिलाफ भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के थानों में डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत करीब 11 मामले दर्ज थे। दोनों ही बदमाश बावरिया गिरोह के सक्रिय सदस्य माने जाते थे, जो अपनी क्रूरता और संगठित अपराध के लिए कुख्यात है।

# जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण का शुभारंभ

आर्यावर्त संवाददाता

**जौनपुर।** जिला जनगणना अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 परमानंद झा की उपस्थिति में कैंप कार्यालय में प्रमुख जनगणना अधिकारी/जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने डिजिटल माध्यम से सूचनाओ को भर कर स्व जनगणना कार्यक्रम का शुभारंभ किया व जनपदवासियों से अपील किया है कि वह भी इसमें अवश्य सहभागिता करे। स्व-गणना 07 मई से 21 मई तक होगी। इसके पोर्टल पर 33 बिंदु पर सूचना मांगी जाएगी, जिसे भली भांति भरते हुए सबमिट करना होगा इसके पश्चात 10 अंकों का एसई-आईडी जनरेट होगा जिसे सुरक्षित कर अपने पास रखना होगा। 22 मई 2026 से 20 जून 2026 की अवधि में मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक के समक्ष इसे प्रस्तुत करना होगा। जिला जज

श्री सुशील कुमार शशि, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने भी स्व जनगणना में डिजिटल माध्यम से अपना विवरण भरा। उनके साथ जनगणना के नोडल अधिकारी युवराज गर्ग भी उपस्थित रहे। सभी तहसीलों, विकासखंड तथा ग्राम पंचायत में स्व-गणना कैंप लगाते हुए लोगों को डिजिटल माध्यम से स्व-गणना करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है तथा स्व गणना करने में उनकी सहायता भी की जा रही है जिससे इस प्रक्रिया में सभी की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाडिया की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में विकास भवन स्थित समस्त कार्यालयों के अधिकारियों/कार्मिकों की जनगणना 2027 के कुशल संचालन,व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्व-गणना के लिए पोर्टल लॉगइन करने हेतु समस्त स्टेप की बारीकियों पर विस्तार से समझाते हुए सभी को अपना एवं अपने परिजनों का स्व-गणना करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए निर्देशित किया गया।

# 'मार दिया तेरा शेर...' ग्रेटर नोएडा में एलएलबी छात्र की हत्या के बाद महिला ने क्यों कही ये बात?

आर्यावर्त संवाददाता

**ग्रेटर नोएडा।** उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एलएलबी छात्र साजन भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस घटना का करीब 3 मिनट 5 सेकंड का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में दो पड़ोसी परिवारों के बीच बढ़ती दुश्मनी, मारपीट और फिर गोली की आवाज साफ सुनाई देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गोली चलाने के बाद आरोपी पक्ष की महिला कथित तौर पर मृतक के दादा से कहती सुनाई देती है, 'मार दिया तेरा शेर'। यही शब्द पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है।

### किस विवाद से शुरू हुआ खूनी खेल?

पुलिस के अनुसार, सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के साकीपुर गांव में रहने वाले 25 वर्षीय साजन भाटी का

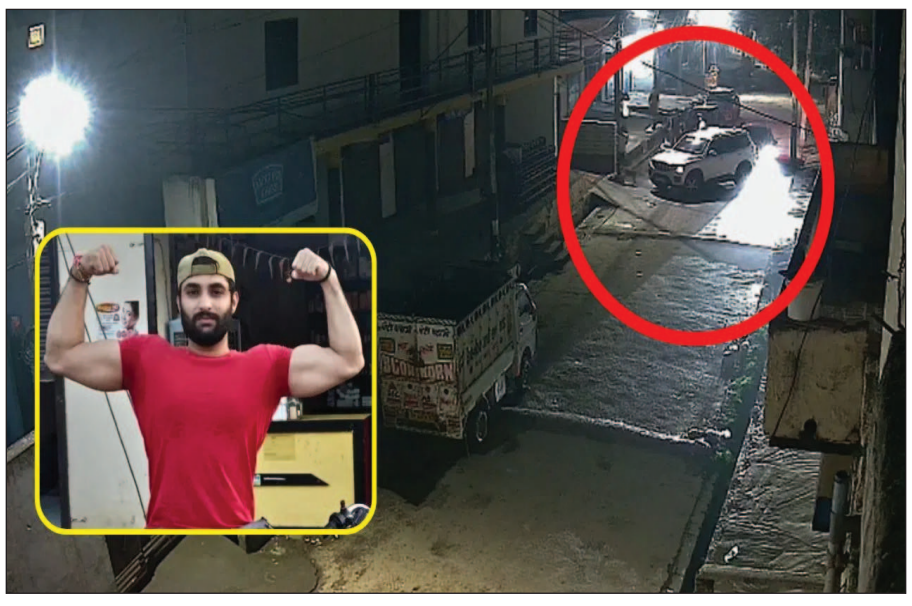

चार दिन पहले पड़ोसी मंगेश उर्फ टिल्लू और उसके परिवार से नाली के पास कूड़ा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। स्थानीय लोगों ने उस समय मामला शांत करा दिया, लेकिन दोनों परिवारों के बीच तनाव लगातार बना रहा।

मंगलवार रात करीब 12:30 बजे साजन एक शादी समारोह से लौटकर घर पहुंचा। आरोप है कि मंगेश पहले से अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर मौजूद था। जैसे ही साजन वहां पहुंचा, उसके ऊपर टिप्पणी की गई। विरोध करने पर कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया।

परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी मंगेश उर्फ टिल्लू ने तमंचा निकालकर साजन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साजन को तीन गोलियां लगीं, जिसमें दो पेट में और एक जांघ के ऊपरी हिस्से में लगी। गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

परिवार के लोग गंभीर हालत में साजन को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साजन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार सुबह अस्पताल के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई।

### एक साल पहले हुई थी शादी

घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 3 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो के आखिरी 1 मिनट 47 सेकंड सबसे अहम बताए जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आमने-सामने खड़े हैं। पहले बहस होती है, फिर धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है। इसके बाद अचानक फायरिंग होती है और लोग इधर-उधर भागने लगते हैं।

वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि गोली चलने के बाद मृतक के दादा घर से बाहर आते हैं और आरोपी पक्ष का विरोध करते हैं। इसी दौरान आरोपी पक्ष की एक महिला कहती है, 'मार दिया तेरा शेर'। इस एक वाक्य ने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है।

मृतक के भाई बॉबी ने बताया कि साजन भाटी की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। परिवार पहले ही एक बड़े दुख से गुजर चुका था। करीब एक साल पहले साजन के पिता की मौत हो चुकी थी। ऐसे में बेटे की हत्या ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। इस पूरे हत्याकांड के बाद गांव में मातम का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।

### गांव में भारी पुलिस बल तैनात

हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ सकता है। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर मुख्य आरोपी मंगेश उर्फ टिल्लू, उसके भाई, मां और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हत्या के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी मंगेश उर्फ टिल्लू को पुलिस ने बुधवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सेंट्रल जोन शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, मोजर बेयर गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने उसके पास से अवैध पिस्टल और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है। इसके अलावा उसके भाई वीर सिंह को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है।

### इलाके में दहशत, ग्रामीणों में गुस्सा

साकीपुर गांव में इस हत्याकांड के बाद डर और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मामूली विवाद में जिस तरह खुलेआम गोलीबारी हुई, उसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीणों की मांग है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है।

# महिलाओं को खूब पसंद आ रहे लूज फिट कपड़े, काफ्तान से ओवरसाइज्ड...ये हैं बेस्ट 5 ऑप्शन

फैशन हर कुछ समय के बाद बदलता रहता है। जैसे इस वक्त लूज फिट कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है। जिसमें महिलाओं को खासतौर पर ढीले-ढाले कपड़े पसंद आ रहे हैं। इसमें काफ्तान से लेकर ओवरसाइज्ड टी-शर्ट।। ट्रेंड में है। चलिए आपको बताते हैं लूज फिट कपड़ों के 5 बेस्ट ऑप्शन।

फैशन की दुनिया में आए दिन नए-नए बदलाव देखने को मिलते हैं। इस वक्त लूज फिट कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है। जिसे खासतौर पर महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद कर रही हैं। जहां पहले फिटेड कपड़े पसंद किए जाते थे। वहीं अब महिलाएं ढीले-ढाले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद कर रही हैं। ये न सिर्फ कंफर्टेबल लगते हैं। बल्कि काफी स्टाइलिश भी लगते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि हर बॉडी टाइप पर सूट करते हैं। सोशल मीडिया और फैशन इन्फ्लुएंसर्स के बीच भी इस ट्रेंड का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है, जिससे यह और तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है।

अगर आप भी अपने वॉर्डरोब में कुछ ऐसा शामिल करना चाहती हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ बेहद आरामदायक भी हो, तो लूज फिट कपड़े आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। काफ्तान से लेकर ओवरसाइज्ड शर्ट्स और फ्लोई ड्रेसेस तक, ऐसे कई ऑप्शन हैं जो इन दिनों ट्रेंड में हैं और महिलाओं को खूब पसंद भी आ रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बेस्ट लूज फिट आउटफिट्स के बारे में, जो आपके देंगे कंफर्ट और स्टाइल।

### काफ्तान

ढीले कपड़ों में काफ्तान महिलाओं की पहली पसंद बन गया है। ये पहनने में काफी कंफर्टेबल होता है और दिखने में बेहद स्टाइलिश। इसका फ्लोई और आरामदायक डिज़ाइन गर्मियों के लिए परफेक्ट माना जाता है। चाहे घर पर पहनना हो या बीच वेकेशन पर स्टाइलिश दिखना हो, काफ्तान हर मौके पर अच्छा लगता है। हल्के फैब्रिक और खूबसूरत प्रिंट्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

### ओवरसाइज्ड शर्ट

ओवरसाइज्ड शर्ट और टीशर्ट का तो क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। पुरुष हो या महिलाएं इसे खूब पसंद कर रही हैं। ये एक ऐसा फिट है जिसे आप कई तरह से स्टाइल कर सकती हैं। फिर चाहे जींस हो, शॉर्ट्स हो या फिर स्कर्ट। यह आपको कूल और कैजुअल लुक देता है, साथ ही पूरे दिन आराम भी देता है। खास बात यह है कि इसे ऑफिस और आउटिंग दोनों के लिए आसानी से कैरी किया जा सकता है।

### लूज फिट जींस या प्लाजो

पहले जहां महिलाएं टाइट जींस पहनना पसंद करती थीं। वहीं, अब उन्हें लूज प्लाजो, लूट फिज जींस और कोरियन पैंट्स पसंद आने लगी हैं। ये काफी आरामदायक होती हैं, जिसे आप टीशर्ट, शॉर्ट कुर्ती या फिर लॉन्ग कुर्ती के साथ भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं। यह खासकर गर्मियों और फेस्टिव सीजन में काफी पसंद किया जाता है।

### मैक्सी ड्रेस

मैक्सी ड्रेस उन महिलाओं के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश दिखना चाहती हैं। इसकी लंबी और ढीली फिटिंग आपको एलिगेंट लुक देती है और साथ ही काफी कम्फर्टेबल भी होती है। कैजुअल डे आउट हो या डिनर प्लान, मैक्सी ड्रेस हर मौके के लिए फिट बैठती है।

### को-ऑर्ड सेट

को-अर्ड सेट तो आजकल महिलाओं की पहली पसंद बना हुआ है। इसमें आपको ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें टॉप और बॉटम दोनों एक ही पैटर्न या कलर में होते हैं, जो आपको एक क्लीन और ट्रेंडी लुक देता हैं। लूज फिटिंग वाले को-ऑर्ड सेट न सिर्फ स्टाइलिश दिखते हैं, बल्कि पहनने में भी बेहद आरामदायक होते हैं। इन्हें आप ट्रैवल, कैजुअल आउटिंग या डे-टू-डे वियर के लिए चुन सकती हैं।

## एयर कूलर की इन तरीकों से करें सफाई, लंबे समय तक मिलेगा फायदा

गर्मियों के दौरान घर को ठंडा रखने में एयर कूलर काफी मदद कर सकता है। हालांकि, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे घर को ठंडक देने के बजाय गर्मी महसूस होने लगती है। इसके अलावा एयर कूलर की लगातार इस्तेमाल से इसके पंखे के ब्लेड और पानी के पंप में गंदगी जमने लगती है, जिससे इसका ठंडक देने का असर कम हो जाता है।

### एयर कूलर की बाहरी सफाई करें

एयर कूलर की बाहरी सफाई के लिए सबसे पहले इसे बंद कर दें, फिर इसके पंखे के ब्लेड, जाली और सामने के हिस्से को गर्म पानी और लिक्विड साबुन से साफ करें। इसके अलावा एयर कूलर के बाहरी हिस्से पर लगे धूल के कणों को हटाने के लिए उसे कपड़े से पोंछें। अगर आपके एयर कूलर पर कोई निशान है तो उसे हटाने के लिए टूथपेस्ट और पानी का मिश्रण बनाकर उससे साफ करें। इससे कूलर चमकदार दिखेगा।

### एयर कूलर के पानी की टंकी को ऐसे करें साफ

एयर कूलर के पानी की टंकी को साफ करने के लिए सबसे पहले इसे बंद करें, फिर टंकी के पानी को बाहर निकालकर इसे गर्म पानी से भरें। इसके बाद टंकी में 2-3 कप सफेद सिरका डालें और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद टंकी को पानी से भरकर उसका पानी बाहर निकाल दें। इस तरह से टंकी की सफाई से इसमें मौजूद गंदगी दूर हो जाएगी।

### एयर कूलर के पानी के पंप की सफाई भी है जरूरी

एयर कूलर के पानी के पंप के लिए गर्म पानी और लिक्विड साबुन का घोल बनाकर उसमें एक कपड़ा भिगोएं, फिर उससे पानी के पंप को साफ करें। इसके अलावा पानी के पंप की सफाई के लिए आप टूथपेस्ट और पानी के मिश्रण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पानी के पंप की सफाई के साथ-साथ एयर कूलर की ठंडक देने की क्षमता भी बढ़ेगी।

### एयर कूलर के पंखे को ऐसे करें साफ

एयर कूलर के पंखे को साफ करने के लिए सबसे पहले इसे बंद करें, फिर एक गीला कपड़ा लेकर उससे पंखे के ब्लेड को साफ करें। इसके बाद पंखे के ब्लेड पर टूथपेस्ट और पानी का मिश्रण लगाएं, फिर एक सूखे कपड़े से पंखे को पोंछ लें। अगर आप पंखे को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए सिरके और पानी के घोल का इस्तेमाल करें।

# गर्मियों में ब्लूबेरी से बने ये 5 पेय बुझाएंगे आपकी प्यास, देंगे भरपूर ताजगी

ब्लूबेरी एक ऐसी बेरी है, जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन-सी, विटामिन-के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस लेख में हम आपको ब्लूबेरी से बनाए जाने वाले कुछ पेय की रेसिपी बताएंगे, जो गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें बनाना आसान है। इन पेय को बनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। ये आपको भरपूर ताजगी भी प्रदान करेंगे।

### ब्लूबेरी और पुदीने का ठंडा पेय

ब्लूबेरी और पुदीने का ठंडा पेय एक ताजगी भरा विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ताजा ब्लूबेरी को पीस लें, फिर इसमें थोड़ी पुदीने की पत्तियां डालकर अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण को छानकर इसमें ठंडा पानी मिलाएं और स्वादानुसार चीनी डालें। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसे पीने से आपको हाइड्रेटेड भी महसूस होगा।

### ब्लूबेरी और नारियल पानी का शेक

ब्लूबेरी और नारियल पानी का शेक एक पौष्टिक पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ ताजा ब्लूबेरी को पीस लें, फिर इसमें नारियल पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा घिसा हुआ नारियल डालें और बर्फ के टुकड़े डालें। यह शेक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ताजगी भरी ऊर्जा देंगे।

### ब्लूबेरी और दही की लस्सी

ब्लूबेरी और दही की लस्सी एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे आप नए अंदाज में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दही को मथकर उसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं। इसके बाद इसमें पिसी हुई ब्लूबेरी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को लंबे गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा इलायची पाउडर छिड़कें और बर्फ के टुकड़े डालें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।

### ब्लूबेरी और अदरक का ठंडा पेय

ब्लूबेरी और अदरक का ठंडा पानी एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ ताजा ब्लूबेरी को मसलकर पानी में डालें, फिर इसमें थोड़ी-सी कद्दूकस की हुई अदरक मिला दें। अब इस मिश्रण को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि इसका स्वाद अच्छे से मिल जाए। यह पेय आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा और आपको ताजगी भरी ऊर्जा देगा।

### ब्लूबेरी और संतरे का रस

ब्लूबेरी और संतरे का रस एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संतरे का रस निकाल लें और उसमें कुछ पिसी हुईं ब्लूबेरी मिला दें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सारे तत्व अच्छे से मिल जाएं। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह रस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि विटामिन-सी से भरपूर भी है।

### ब्लूबेरी और

# सब्जियों में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल की पहचान करने में काम आएंगी ये टिप्स

अक्सर बाजार में सब्जियों को कृत्रिम रंग से चमकदार बनाया जाता है। इससे वे देखने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि सब्जियां ताजी हैं या नहीं। आज हम आपको कुछ सरल तरीके बताने वाले हैं, जिनसे आप सब्जियों की ताजगी का पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि उनमें कृत्रिम रंग इस्तेमाल हुए हैं या नहीं।

### सब्जियों की खुशबू और रंग से लगाएं पता

जब आप सब्जियां खरीदें, तो उन्हें सूंघकर देखें। ताजा सब्जियों की महक अच्छी होती है, जबकि कृत्रिम रंगों से रंगी हुई सब्जियों में कोई खास खुशबू नहीं होती। इसके अलावा ताजा सब्जियां छूने पर नरम महसूस होती हैं, जबकि रंगी हुई सब्जियां सख्त होती हैं। आप उंगली से घिसकर भी देख सकते हैं कि कहीं सब्जी का रंग उतर तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो तो सब्जी का सेवन न करें।

### काटकर देखें

सब्जियों को काटकर भी आप उनकी ताजगी की जांच कर सकते हैं। ताजा सब्जियों को काटने पर जो रस निकलता है वह हल्का होता है, जबकि रंगी हुई सब्जियों का रस गहरा होता है। अगर सब्जियों को काटने पर रस नहीं निकलता, तो वे कृत्रिम रंग वाली हो सकती हैं। साथ ही ऐसी सब्जियों को काटने पर वे अंदर से ताजा नहीं लगती हैं, जो एक सीधा संकेत है कि उन्हें रासायनिक प्रक्रिया से पकाया गया है।

### स्वाद से पहचानें

सब्जियों का स्वाद चखकर भी उनकी ताजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर स्वाद कड़वा या अजीब लगता है तो संभव है कि उसमें रंग का इस्तेमाल हुआ हो। ताजा सब्जियों का स्वाद अच्छा और प्राकृतिक होता है, जो किसी भी तरह से रासायनिक नहीं लगता है। साथ ही जब आप ऐसी सब्जियों को पकाते हैं तो भी उनका रंग आसानी से उतरने लगता है। पकाने के बाद उनकी बनावट भी बदल सकती है।

### सब्जियों को छीलने से भी चल जाएगा पता

सब्जियों को छीलकर भी उनकी ताजगी देखी जा सकती है। अगर छिलके का रंग बदल जाता है, तो समझिए कि उसमें रंग का इस्तेमाल हुआ है। ताजा सब्जियों का छिलका अपने असली रंग में रहता है, चाहे आप उसे छीलने से पहले साफ भी कर लें। इन तरीकों से आप सब्जियों की ताजगी आसानी से पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि वे कृतिम रंगों से तो नहीं रंगी गई हैं।

# AI अपनाने की अंधी दौड़ में कंपनियों पर मंडराया खतरा, बुनियादी ढांचे की कमी से बढ़ा साइबर अटैक का जोखिम

**जोहो कॉर्प की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियां तेजी से एआई अपना रही हैं, लेकिन बुनियादी सुरक्षा ढांचे की कमी के कारण उन पर साइबर हमलों का भारी खतरा है। 93% कंपनियां एआई को सुरक्षा के लिए अच्छा मानती हैं, लेकिन हर तीसरी कंपनी ने अभी तक मजबूत 'जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क' लागू नहीं किया है। आइए, विस्तार से पूरी रिपोर्ट को जानते हैं...**

तकनीक की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में भारत की कई कंपनियां एक बहुत बड़े और गंभीर खतरे की तरफ बढ़ रही हैं। आज के समय में हर छोटी-बड़ी कंपनी अपने काम को आसान, तेज और आधुनिक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का जमकर सहारा ले रही है। लेकिन, इस अंधी दौड़ में वे अपनी सबसे अहम चीज यानी बुनियादी सुरक्षा को पूरी तरह से भूलती जा रही हैं। कंपनियों के पास साइबर हमलों से बचने के लिए जो एक मजबूत और ठोस बुनियादी सुरक्षा ढांचा होना चाहिए, उसकी भारी कमी साफ नजर आ रही है। इसी लापरवाही के कारण कंपनियों पर बड़े साइबर हमलों का भारी खतरा मंडरा रहा है। यह चौंकाने वाला खुलासा जाने-माने सॉफ्टवेयर संगठन जोहो कॉर्प की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है।

जोहो कॉर्प द्वारा जारी की गई 'स्टेट ऑफ वर्कफोर्स पासवर्ड सिक्योरिटी रिपोर्ट-2026' में कंपनियों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 93 प्रतिशत संगठन यह तो मानते हैं कि एआई का इस्तेमाल उनकी साइबर सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि देश की हर तीन में से एक कंपनी अब तक 'जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क' यानी आधुनिक साइबर सुरक्षा का ढांचा ही अपने यहां लागू नहीं कर पाई है। जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क का सीधा सा मतलब है किसी पर भी आसानी से भरोसा न करना और हर स्तर पर सुरक्षा की कड़ी जांच करना। इस अहम ढांचे के लागू न होने की वजह से ही शातिर साइबर ठगों के लिए इन कंपनियों के जरूरी डेटा में सेंध लगाना बहुत आसान होता जा रहा है।

## भारतीय कंपनियां साइबर हमलों से बचने के लिए क्या कर रहीं?

टिगॉन एडवायजरी कॉर्प की तरफ से जोहो वॉल्ट के लिए दुनिया भर में किए गए इस विस्तृत वैश्विक सर्वे में एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। यह अंतर भारतीय कंपनियों के सुरक्षा को लेकर उनके अति-आत्मविश्वास और उनकी असली तैयारियों के बीच का है। रिपोर्ट के अनुसार, 98 प्रतिशत भारतीय कंपनियां एआई पर आधारित नए सुरक्षा टूल्स को अपनाने की जोरदार योजना बना रही हैं। इसमें से 76 प्रतिशत कंपनियों का सबसे पहला ध्यान 'रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स' पर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वे ऐसी आधुनिक तकनीक चाहती हैं जो किसी भी साइबर खतरे को तुरंत पहचान ले और उसी वक्त उसका करारा जवाब भी दे सके।

## कंपनियों के लिए तकनीक पहले, सुरक्षा बाद में

सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की इस तेज दौड़ में 56 प्रतिशत कंपनियों का ध्यान 'यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स' पर है, यानी वे यह गहराई से समझना चाहती हैं कि सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है। वहीं, 55 प्रतिशत कंपनियां जोखिम पर आधारित 'एक्सेस कंट्रोल ऑटोमेशन' पर फोकस कर रही हैं, जिससे उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप बिना किसी इंसानी मदद के काम कर सके। लेकिन, इस पूरी अत्याधुनिक योजना में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन तकनीकों को अपनाने की चाहत तो बहुत है, लेकिन कंपनियों की जो सबसे बुनियादी सुरक्षा स्थिति है, वह अभी भी बहुत कमजोर बनी हुई है। बिना मजबूत नींव के ये तकनीकें बेअसर हैं।

## कंपनियां पहले ही हो चुकी साइबर हमलों का शिकार?

इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही डराने वाला और कड़वा सच सामने आया है। सर्वे में यह स्पष्ट पता चला है कि लगभग 47 प्रतिशत कंपनियां पहले ही किसी न किसी तरह के गंभीर साइबर हमलों का शिकार हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन कंपनियों को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी हैकर या दुश्मन से नहीं, बल्कि 'इनसाइडर थ्रेट' यानी अपने ही अंदरूनी लोगों से है। 23 प्रतिशत कंपनियों ने खुलकर माना है कि उन्हें अपने ही कर्मचारियों या सिस्टम से जुड़े लोगों से प्रमुख जोखिम बना हुआ है। इसके अलावा, 18 प्रतिशत खतरा रैनसमवेयर (डेटा चुराकर फिरौती मांगना) और 18 प्रतिशत खतरा इंसानी गलतियों (मानवीय त्रुटियों) से है।

# करोड़ों यूजर्स को शाओमी का झटका, हमेशा के लिए बंद करने जा रहा ये शानदार स्मार्टफोन, वजह जानकर लगेगा बड़ा धक्का

स्मार्टफोन बाजार में अपने किफायती और दमदार फोन्स के लिए पहचानी जाने वाली दिग्गज चीनी कंपनी शाओमी ने अपने करोड़ों फैंस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। टेक जगत की ताजा रिपोर्ट्र्स के मुताबिक, कंपनी अब अपने एक बेहद लोकप्रिय फोल्डेबल (फ्लिप) फोन लाइनअप को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस साल कंपनी अपने फ्लिप फोन का कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं करेगी और भविष्य में भी इसके अगले वेरिएंट्स को हमेशा के लिए 'गुड बाय' कहा जा सकता है।

## फ्लिप सीरीज पर हमेशा के लिए लगा ग्रहण!

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर मशहूर टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस चौंकाने वाली खबर का दावा किया है। एक यूजर द्वारा शाओमी के अगले फ्लिप फोन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डीसीएस ने स्पष्ट किया कि कंपनी अब छोटे फोल्डेबल फोन यानी मिक्स फ्लिप को आगे लॉन्च नहीं करेगी। हालांकि, इस रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि कंपनी अपने बड़े बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन 'मिक्स फोल्ड' को बंद करेगी या नहीं, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे बड़े फोल्डेबल फोन लवर्स को थोड़ी राहत जरूर है।

## आखिर कंपनी ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

शाओमी की तरफ से अपनी पूरी फ्लिप प्रोडक्ट लाइन को रातों-रात बंद करने के इस बड़े फैसले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन, सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो छोटे फोल्डेबल फोन (फ्लिप फोन) को बनाने में आने वाली भारी प्रोडक्शन लागत इसका मुख्य कारण है। अधिक लागत और बाजार में उस स्तर का 'वैल्यू प्रोपोजिशन' (मुनाफा और ग्राहकों का रुझान) न मिल पाने के कारण कंपनी को इसमें घाटा नजर आ रहा है, जिसके चलते इस सीरीज को हमेशा के लिए समेटने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

## शाओमी ही नहीं, ओप्पो ने भी खींचे अपने हाथ

ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाओमी ही अपने फ्लिप फोन से तौबा कर रही है। इससे पहले चीनी कंपनी ओप्पो ने भी अपनी फ्लिप फोन सीरीज को आगे नहीं बढ़ाने का मन बना लिया है। ओप्पो ने साल 2023 में फाइंड एन3 फ्लिप लॉन्च किया था, जिसके बाद उसका कोई नया मॉडल बाजार में नहीं उतारा गया है। हालांकि दूसरी तरफ, मोटोरोला लगातार इस सेगमेंट में दांव खेल रही है। हाल ही में मोटोरोला ने रेजर 70 (क्रङ्ड5ह्म् 70), रेजर 70+ और रेजर 70 अल्ट्रा को बाजार में उतारा है, जिन्हें आने वाले कुछ सप्ताह में सेल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

## अब नए बड़े फोल्डेबल फोन से है शाओमी को उम्मीद

फ्लिप फोन को भले ही शाओमी अलविदा कह रही हो, लेकिन कंपनी अपने बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करने की पूरी तैयारी में है। जानकारी के अनुसार, शाओमी का अगला धांसू फोल्डेबल फोन इसी साल जुलाई या अगस्त के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन बाजार में 'मिक्स फोल्ड 6' या फिर 'शाओमी 17 फोल्ड' के नाम से दस्तक दे सकता है, जिसमें परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अत्याधुनिक ङ्गह्म्द्बठ्ठद्द ह्3 चिपसेट मिलने की पूरी उम्मीद है।

# अमेरिकी अदालत से भारतीय मूल के विशेषज्ञ एशले को बड़ी राहत, जासूसी कानून का मामला खारिज

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** भारतीय मूल के विशेषज्ञ एशले जे. टेलिस के खिलाफ चल रहे जासूसी कानून से जुड़े मामले में अमेरिकी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्जीनिया की एक संघीय अदालत ने तकनीकी कानूनी आधार पर यह मामला खारिज कर दिया। अदालती आदेश में कहा गया कि याचिका स्वीकार की गई और मामला बिना किसी पूर्वाग्रह के खारिज किया गया। अमेरिका के वर्जीनिया स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज माइकल एस. नाचमैनॉफ ने 16 अप्रैल को टेलिस की याचिका स्वीकार करते हुए केस को खारिज करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने गलत कानूनी प्रावधान के तहत आरोप लगाए थे।



टेलिस अमेरिका की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज अपने निजी घर में रखे थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक टेलिस ने अमेरिकी विदेश विभाग और रक्षा तंत्र से जुड़े वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए कई संवेदनशील दस्तावेज अपने पास रखे।

सरकार की ओर से दायर आरोपपत्र में कहा गया था कि टेलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 11 गोपनीय फाइलें अपने निजी निवास पर हार्ड कॉपी और डिजिटल फॉर्म में रखीं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी उच्चस्तरीय पहुंच का फायदा उठाकर सुरक्षित सरकारी कार्यस्थलों से राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी जानकारी बाहर निकाली और उसे निजी तौर पर संग्रहीत किया।

## टेलिस ने क्या दी दलील?

हालांकि टेलिस की कानूनी टीम ने अदालत में दलील दी कि सरकार ने जासूसी अधिनियम की गलत धारा के तहत मामला दर्ज किया। उनके वकीलों का कहना था कि जिस धारा 793(e) के तहत उन पर आरोप लगाए गए, वह केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिनके पास गोपनीय दस्तावेज अनधिकृत रूप से हों। जबकि सरकार खुद मान रही थी कि टेलिस के पास उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी थी और उन्हें इन दस्तावेजों तक अधिकृत पहुंच प्राप्त थी।

बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि टेलिस को संबंधित दस्तावेज आधिकारिक रूप से सौंपे गए थे, इसलिए उन्हें अवैध कब्जा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने उन पर गोपनीय जानकारी लीक करने या अपनी मंजूरी से बाहर जाकर दस्तावेज हासिल करने का आरोप भी नहीं लगाया।

कानूनी टीम ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष चाहे तो जासूसी कानून की दूसरी धारा 793(d) या धारा 1924 के तहत मामला दर्ज कर सकता था, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा गोपनीय दस्तावेज हटाने और रखने से संबंधित है। लेकिन सरकार ने जानबूझकर गलत प्रावधान चुना।

इससे पहले संघीय अभियोजकों ने टेलिस की जमानत शर्तों में ढील देने का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि टेलिस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और फरार होने का जोखिम बने हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि उनके पास हजारों पन्नों के गोपनीय दस्तावेज थे, जिनमें 1,000 से ज्यादा पन्ने टॉप सिक्रेट श्रेणी के थे। सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ दस्तावेज चीन की परमाणु और सैन्य क्षमताओं से जुड़े थे। अभियोजकों का कहना था कि टेलिस के पास दशकों की संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी मौजूद थी।

मामला खारिज होने के बाद टेलिस ने अदालत में अपनी जमानत राशि वापस करने की मांग की, जिस पर सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं अदालत ने जांच के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस करने की उनकी मांग पर भी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले ने वॉशिंगटन के रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हलकों में काफी ध्यान खींचा, क्योंकि टेलिस लंबे समय तक अमेरिकी सरकार को रक्षा और इंडो-पैसिफिक नीति पर सलाह देते रहे हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका में गोपनीय दस्तावेजों के गलत तरीके से रखे जाने के मामलों पर सख्ती बढ़ी है। मौजूदा और पूर्व सरकारी अधिकारियों द्वारा संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज संभालने को लेकर कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच चल रही है।

# ईरान पर US के दो सुर : ट्रंप-रुबियो के विरोधाभासी बयानों से ईरान युद्ध पर बढ़ी अनिश्चितता

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर ही अलग-अलग संकेत सामने आने लगे हैं। एक तरफ विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि अभियान अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद समाप्त हो चुका है और अब वॉशिंगटन वार्ता के जरिए समाधान चाहता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान प्रस्तावित समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो सैन्य हमले फिर शुरू हो सकते हैं और उनकी तीव्रता पहले से अधिक होगी। इसी बीच होर्मुज जलमार्ग में जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया अमेरिकी मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम भी फिलहाल रोक दिया गया है। इन घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम एशिया में तनाव अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब संघर्ष सैन्य मोर्चे से कूटनीतिक दबाव की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। अल जजीरा व अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का उद्देश्य पूरा हो चुका है और अमेरिका अब किसी नए सैन्य टकराव के बजाय समझौते का रास्ता तलाशना चाहता है। उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। पिछले महीने इस्लामाबाद में हुई प्रारंभिक वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, पर दोनों देशों ने बाद में नए प्रस्ताव एक-दूसरे को भेजे हैं। रुबियो के अपेक्षाकृत नरम बयान के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, ऑपरेशन तभी पूरी तरह समाप्त माना जाएगा जब ईरान तय शर्तों को स्वीकार करेगा।

# अंतरिक्ष में धरती से 30% बड़े सुपर-अर्थ की खोज, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार किया ग्रह की सतह का अध्ययन

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अंतरिक्ष विज्ञान में एक अहम उपलब्धि हासिल करते हुए वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी दूरस्थ चट्टानी ग्रह की सतह का विस्तृत अध्ययन किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किए गए इस शोध में एलएचएस 3844 बी नाम के एक सुपर-अर्थ के ऐसे संकेत मिले हैं, जो उसे हमारे सौरमंडल के बुध ग्रह जैसा बनाते हैं। यह ग्रह अत्यधिक गर्म, अंधकारमय और पूरी तरह निर्जीव माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सतह पर न तो कोई वातावरण है और न ही जीवन के अनुकूल परिस्थितियां। यह अध्ययन नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

यह पहली बार है जब किसी दूरस्थ चट्टानी ग्रह की सतह और उसकी भूगर्भीय संरचना का इतने विस्तार से अध्ययन किया गया है। यह खोज संकेत देती है कि भविष्य में दूसरे ग्रहों की जमीन व उनके भूगर्भीय इतिहास को भी समझना संभव होगा। एलएचएस 3844 बी पृथ्वी से 48.5 प्रकाश-वर्ष दूर है और आकार में पृथ्वी से करीब 30 प्रतिशत बड़ा है। इसे सुपर-अर्थ श्रेणी में रखा जाता है।



## क्या होते हैं सुपर-अर्थ ग्रह?

सुपर-अर्थ ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जो आकार में पृथ्वी से बड़े होते हैं, लेकिन गैसीय दानव ग्रहों जितने विशाल नहीं होते। यह ग्रह अपने तारे के बेहद करीब परिक्रमा करता है और केवल 11 घंटे में उसका एक चक्कर पूरा कर लेता है।

## ग्रह पर नहीं मिला वातावरण का कोई संकेत

शोध में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि एलएचएस 3844 बी पर पृथ्वी जैसी गैसीय परत नहीं है, जो तापमान नियंत्रित कर सके या सतह को बाहरी विकिरण से बचा सके। वातावरण के अभाव में यह ग्रह सीधे अंतरिक्षीय विकिरण और उल्कापिंडों के प्रभाव का सामना करता है।

## बेसाल्ट चट्टानों की हो सकती है सतह

शोधकर्ताओं के अनुसार एलएचएस 3844 बी की सतह पृथ्वी जैसी नहीं है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इसकी सतह बेसाल्ट चट्टानों से बनी हो सकती है। बेसाल्ट वह चट्टान होती है जो ज्वालामुखीय लावा के ठंडा होने से बनती है।

## एमआईआरआई उपकरण महत्वपूर्ण

अध्ययन में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर लगे एमआईआरआई यानी मिड-इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने अहम भूमिका निभाई। यह उपकरण इन्फ्रारेड रोशनी का विश्लेषण कर दूरस्थ ग्रहों की सतह व तापीय गुणों का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक इस ग्रह की सीधी तस्वीर नहीं ले सके, इसलिए उन्होंने ग्रह और उसके तारे से आने वाली रोशनी में सूक्ष्म बदलावों का विश्लेषण किया। 5 से 12 माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली इन्फ्रारेड रोशनी के अध्ययन से एक विस्तृत स्पेक्ट्रम तैयार किया गया, जिससे सतह की प्रकृति का पता चला।

# यौन शोषण-मानहानि मामला : 'लेखिका को फिलहाल हर्जाने की राशि लेने से रोकें', ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में अपील

**न्यूयॉर्क, एजेंसी।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेखिका ई जीन कैरोल को 8.3 करोड़ डॉलर देने के अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रंप के वकील ने न्यूयॉर्क की एक अपील कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील पूरी होने तक यह रकम न दिलाई जाए। यह मामला यौन शोषण और मानहानि से जुड़ा है। कैरोल ने आरोप लगाया था कि 1996 में न्यूयॉर्क के एक स्टोर के कपड़े बदलने वाले कक्ष में ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया था।



## लेखिका ने किताब में किया घटना का जिक्र

कैरोल ने 2019 में एक किताब में इस घटना का जिक्र किया। इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से आरोपों को झूठा बताया। कैरोल ने कहा कि ट्रंप के बयानों से उनकी छवि खराब हुई। इसके बाद उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

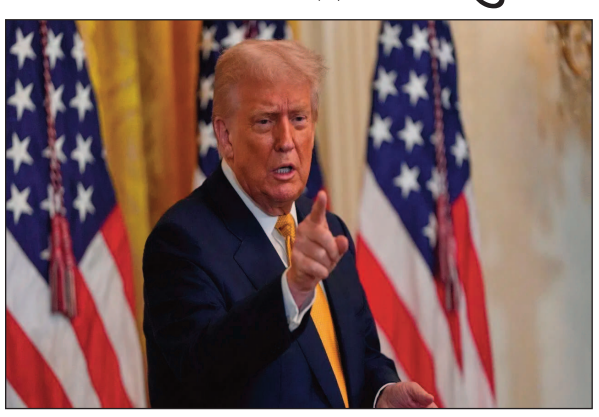

## जूरी ने माना था ट्रंप ने किया यौन शोषण

मई 2023 में एक जूरी ने माना कि ट्रंप ने कैरोल का यौन शोषण किया और बाद में उनकी मानहानि भी की। तब कोर्ट ने कैरोल को 50 लाख डॉलर देने का आदेश दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में एक दूसरी जूरी ने मानहानि मामले में कैरोल को 8.3 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला सुनाया।

## आरोपों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह कैरोल को जानते तक नहीं थे और यह मामला राजनीतिक कारणों से खड़ा किया गया है। अब ट्रंप के वकील जस्टिन डी स्मिथ ने कोर्ट से कहा है कि अगर अभी भुगतान कराया गया तो बाद में पैसे वापस लेना मुश्किल होगा।

## ट्रंप के वकील ने क्या दलील दी?

वकील ने दलील दी कि कैरोल सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि वह यह रकम दान कर देंगी। ट्रंप की कानूनी टीम का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति रहते हुए दिए गए बयानों को लेकर उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं, कैरोल की ओर से कहा गया है कि अगर रोक लगानी है तो ट्रंप को जमानत राशि में 74 लाख डॉलर और जमा कराने होंगे, ताकि ब्याज की रकम सुरक्षित रहे।

# चंद्रनाथ की मां ने की दोषियों के लिए उम्रकैद की मांग, जांच के लिए एसआईटी गठित, इलाके में तनाव

**कोलकाता, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद उनकी मां हसिरानी ने गुरुवार को कहा कि वह चाहती हैं कि दोषियों को सजा मिले। उन्होंने कहा, मैं एक मां हूं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें (दोषियों को) फांसी दी जाए। मैं चाहती हूं कि उन्हें उम्रकैद हो। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि भाजपा सत्ता में आई है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व कई बारे इसे लेकर चिंता जता चुका है। हसिरानी रथ ने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े कुछ लोगों ने पहले भड़काऊ बयान दिए थे और चुनाव के बाद नतीजों को लेकर धमकियों जैसी बातें कही गई थीं।

हसिरानी ने कहा कि अगर उनके बेटे की मौत हादसे में होती तो उन्हें इतना दुख नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या की गई, वह बेहद दर्दनाक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या

को लेकर कई बातें तृणमूल कांग्रेस की ओर से गढ़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराया है, तबसे उनके परिवार को लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, चंद्रनाथ की हत्या पर उनके छोटे भाई देव कुमार ने कहा, जिस किसी ने भी यह साजिश रची है, उसे सबसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमने कल करीब दोपहर दो बजे उनसे बात की थी। देव ने कहा, कल वह (चंद्रनाथ) हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने हमसे बात की थी। दोपहर दो बजे के बाद वह कोलकाता के लिए निकले। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।

### टीएमसी शासन में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हत्या के मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह हत्या राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार (टीएमसी) के शासन में 'कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने' का सबूत है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के विधानसभा चुनावों में सत्ता खोने के बाद टीएमसी 'अराजकता' को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम के 48 घंटे के भीतर अधिकारी के कार्यकारी सहायक चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। एक भाजपा नेता ने कहा, विपक्ष के नेता से करीबी रूप से जुड़े व्यक्ति को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया है। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी सरकार के तहत कानून-व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है, जिसे बंगाल की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। अधिकारी ने गुरुवार को अपने करीबी सहयोगी की हत्या को 'ठंडे दिमाग से की गई हत्या' बताया और आरोप लगाया कि हमलावरों ने उत्तर 24 परगना जिले में हमला करने से पहले पूरी रैकी की थी।

### पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा?

चंद्रनाथ की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने कल केवल एसपी से बात की थी। एक डॉक्टर ने पहले उन्हें सूचित किया था कि चंद्रनाथ को सीने में दो गोलियां लगी हैं। उस समय खुद शुभेंदु अधिकारी को भी पूरी जानकारी नहीं थी। बाद में उन्हें बताया गया कि चंद्रनाथ अब नहीं रहे। उन्होंने इसे बेहद चौंकाने वाली घटना बताया और कहा कि दो दिन बाद होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ऐसी घटना होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित पूरी शीर्ष नेतृत्व टीम पश्चिम बंगाल आ रही है और ऐसे समय में हुई यह घटना स्थिति को अलग नजरिये से देखने पर मजबूर करती है। समिक भट्टाचार्य ने आगे कहा कि कल चार राउंड गोलीबारी में कथित तौर पर तीन पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत हुई और एक अन्य मौत राजारहाट में हुई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के चुनाव जीतने के बावजूद उसके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में 311 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। उन्होंने कई महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने मृतक चंद्रनाथ की मां के बयान की सराहना करते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत के बावजूद उनका संयम और गरिमा में बोलना बेहद असाधारण है।

### हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ: भाजपा नेता अर्जुन सिंह

भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा, सरकार का गठन तुरंत किया जाना चाहिए और स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर उन्होंने कहा, यह जांच का विषय है कि यह चुनाव के बाद की हिंसा है या इसके पीछे (टीएमसी महासचिव) अभिषेक बनर्जी का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित हत्या है, जिसे एक निशानेबाज ने अंजाम दिया। अर्जुन सिंह ने यह भी दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के कुछ पुलिस अफसरों से संबंध हैं, जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है।

### घटना का राजनीतिकरण कर रही भाजपा: टीएमसी

तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा जांच पूरी होने से पहले ही इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से टीएमसी का कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। भाजपा को बेबुनियाद आरोप लगाने से बचना चाहिए। हमने ही इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है।

### कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग

कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर त्रासदी को राजनीतिक लड़ाई में बदल देते हैं। राज्य कांग्रेस के एक नेता ने कहा, अपराधियों की गिरफ्तारी और न्याय सुनिश्चित करने पर फोकस होना चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर।

### माकपा ने बिगड़ते राजनीतिक माहौल पर चिंता जताई

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी इस हत्या की निंदा की और राज्य में बिगड़ते राजनीतिक माहौल पर चिंता जताई। माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, टीएमसी शासन में हिंसा और भय बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रशासन को सख्ती और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। हम इस हत्या की निंदा करते हैं और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इस बीच, मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

# 'शादी कब है?' अफेयर के बीच कथित बॉयफ्रेंड से शादी के सवाल पर हुमा कुरैशी ने दिया ये रिएक्शन

**हुमा कुरैशी अपनी शादी की खबरों को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। जानिए शादी के सवाल पर एक्ट्रेस ने दिया क्या रिएक्शन...**

हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी फिल्मों और सीरीज से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं। एक्टिंग कोच रचित सिंह से अफेयर की चर्चाओं के बीच अब दोनों की शादी की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। हुमा और रचित को अक्सर साथ में देखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बीच हुमा कुरैशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे जब शादी को लेकर सवाल किया गया, तो उनका रिएक्शन अब वायरल है।

### वायरल हो गया हुमा कुरैशी का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर हुमा कुरैशी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हुमा अपने कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ ही नजर आ रही हैं। कपल किसी जगह से साथ में बाहर आते हैं। इस दौरान वहां मौजूद पैपराजी उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद कपल साथ में पोज भी देते हैं। इस दौरान एक पैपराजी हुमा से पूछता है, 'मैम, आपकी शादी कब है?'

पैपराजी के इस सवाल पर हुमा कोई जवाब नहीं देती हैं। वो सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं और सवाल को नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि, इस दौरान हुमा ने रचित के साथ पोज देना जारी रखा। शादी के सवाल पर हुमा का ये रिएक्शन अब वायरल है और लोग उनकी मुस्कुराहट का अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं।

### हुमा-रचित ने रिश्ते पर नहीं की कभी बात

पिछले कई दिनों से हुमा कुरैशी और रचित सिंह के अफेयर की चर्चाएं बी-टाउन का हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। दोनों को अक्सर साथ में ही स्पॉट किया जाता है। हालांकि, अभी तक हुमा या रचित किसी ने अपने रिश्ते पर मोहर नहीं लगाई है। लेकिन हाल ही में उन्हें कई कार्यक्रमों और आउटिंग में एक साथ देखा गया है।

कैमरे पर वे काफी सहज दिखते हैं, जिससे अफवाहें और बढ़ जाती हैं। कुछ खबरों के अनुसार, उनकी सगाई भी हो चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर में किसी के हवाले से कहा गया है कि कपल इस साल के अंत में शादी कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। फैंस को कपल के कंफर्मेशन का इंतजार है।

### हुमा की पाइपलाइन में हैं कई बड़ी फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी आखिरी बार पिछले साल अपनी हिट वेब सीरीज 'महारानी' के चौथे सीजन और 'दिल्ली क्राइम' के तीसरे सीजन में नजर आई थीं। इसके अलावा वो पिछले साल आई फिल्म 'सिंगल सलमा' में भी प्रमुख भूमिका में थीं।वहीं उनके आगामी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हुमा की पाइपलाइन में कई बड़ी फिल्में व प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें यश की मच अवेटे फिल्म 'टॉक्सिक' भी शामिल है। इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में 'बेबी डू डाई डू', 'पूजा मेरी जान' और 'गुलाबी' जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

# मैं वापस आऊंगा से क्या कमाल है गाना रिलीज, दिलजीत दोसांझ और ए. आर. रहमान की जोड़ी ने जीता दिल

दिलजीत दोसांझ और ए। आर। रहमान की आवाज और संगीत से सजा नया गाना 'क्या कमाल है' दर्शकों के बीच आ चुका है। यह खूबसूरत ट्रैक इम्तियाज अली की आगामी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का पहला गीत है, जो उम्मीद और प्रेम का संदेश लेकर आता है।

दो साल पहले फिल्म अमर सिंह चमकीला के जरिए जादू बिखेरने के बाद यह टीम एक बार फिर साथ आई है। इस बार उनके साथ गीतकार इरशाद कामिल भी हैं, जिनकी संवेदनशील लेखनी ने इस गाने को और गहराई दी है। 'क्या कमाल है' सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक एहसास है जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण दिखाता है।

इम्तियाज अली की फिल्मों में संगीत हमेशा कहानी का अहम हिस्सा रहा है, और इस बार भी उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। 'क्या कमाल है' एक सॉन्ग ऑफ होप के रूप में सामने आता है, जो विभाजन काल के दौर में भी जीवित रही मोहब्बत की कहानियों से प्रेरित है। आज के शोर-शराबे और अस्थिरता भरे माहौल में यह गीत हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी प्यार, सुकून और अपनापन बाकी है।

इम्तियाज अली का कहना है आज के समय में जब दुनिया कई तरह के संकटों से गुजर रही है, यह गीत लोगों को सकारात्मकता और उम्मीद देने की कोशिश करता है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को अपने दिल के बेहद करीब बताया। उनके मुताबिक, यह गीत आपको ठहरकर महसूस करने का मौका देता है बिना

किसी बनावट के, पूरी ईमानदारी के साथ।

ए।आर रहमान ने भी इस सहयोग को एक निरंतर रचनात्मक संवाद बताया। उन्होंने कहा, इस फिल्म की थीम जुदाई और विस्थापन को ध्यान में रखते हुए ऐसा संगीत रचा गया है जो शांति और सुकून का अहसास कराए। उनके अनुसार, 'क्या कमाल है' उस खूबसूरती को दर्शाता है जिसे हम अक्सर दुनिया के शोर में नजरअंदाज कर देते हैं।

गीतकार इरशाद कामिल ने इस गाने को एक सपना बताया है ऐसा सपना जिसमें न दर्द है, न डर। उनके शब्दों में, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां सिर्फ प्यार, शांति और उम्मीद हो।

अब बात करते हैं म्यूजिक लेबल की। कुमार तौरानी ने कहा, हम टिप्स में मानते हैं कि संगीत भारतीय सिनेमा की धड़कन है। दिलजीत दोसांझ और ए।आर। रहमान का यह पहला ओरिजिनल कोलैबोरेशन, वह भी इम्तियाज अली की कहानी के साथ, 'क्या कमाल है' को बेहद खास बनाता है। यह गाना श्रोताओं के दिलों से गहराई से जुड़ता है और खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक उनके साथ रहता है। यह हमारे उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें हम मिनींगफुल और आत्मीय संगीत दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं।

फिल्म मैं वापस आऊंगा में दिलजीत दोसांझ के साथ नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म अप्लॉज एंटरटेनमेंट और विंडो सीट फिल्म्स द्वारा निर्मित है, जबकि म्यूजिक टिप्स इंडस्ट्री के तहत रिलीज किया गया है।

यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 'क्या कमाल है' के साथ इस फिल्म ने पहले ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है, और अब सभी को इसके बड़े पर्दे पर आने का बेसब्री से इंतजार है।

# हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट का टीजर रिलीज, डर से उछलने पर मजबूर कर देगी विक्रम भट्ट की ये भूतिया फिल्म

विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3डी 2011 में रिलीज हुई थी, और अब मेकर्स ने इसके बहुप्रतीक्षित सीक्वल हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट का टीजर जारी कर दिया है। टीजर देखकर लगता है कि यह आपको डर से उछलने पर मजबूर कर देगा, लेकिन साथ ही अपनी कहानी से आपकी दिलचस्पी भी जगाएगा।

12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म सीक्वल हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट ने अभी से ही काफी चर्चा बटोरना शुरू कर दिया है। इसे विक्रम भट्ट की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।

विक्रम भट्ट ने अपनी आगामी हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट का टीजर लॉन्च किया, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया है। इस टीजर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, हर प्रेत-बाधा का एक इतिहास होता है। हर चीख अपने साथ एक याद लिए होती है। और हर वो डरावनी कहानी, जिसका अंत बुरा हुआ हो- असल में, एक प्रेम कहानी ही होती है। इंतजार अब खत्म हुआ है। पेश है

हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट ऑफिशियल टीजर।

टीजर की शुरुआत मिमोह से होती है, जो किसी चीज की तलाश में एक महल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। इसके बाद लीड एक्ट्रेस चेतना नजर आती हैं। सीन काफी हद तक डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, लेकिन टीजर किसी भी रहस्य का खुलासा नहीं करता।

टीजर को लेकर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। विक्रम भट्ट के खास अंदाज के फैंस उन्हें उस जॉनर में वापस लौटते देख काफी उत्साहित हैं, वहीं कुछ दर्शक इसे हॉरर की एक ऐसी पुरानी शैली की वापसी मान रहे हैं जो अब शायद पुरानी पड़ चुकी है। फिर भी, लोगों में इसे लेकर उत्सुकता जबरदस्त है, और हॉरर फिल्मों के शौकीन यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या यह फिल्म पुरानी यादों और नएपन के बीच सही तालमेल बिठा पाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इसमें 3डी टेक्नोलॉजी में सबसे नए डेवलपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है कि यह फिल्म ज्यादा इंटेंस और इमर्सिव हॉरर एक्सपीरियंस देगी।

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे, मिमोह चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। हेमंत पांडे, गौरव बाजपेयी, प्रणीत भट्ट, चेतना पांडे और श्रुति प्रकाश भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका निर्देशन आनंद पंडित और राकेश जुनेजा ने किया है। जबकि इस फिल्म का निर्माण प्रोमोएज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com